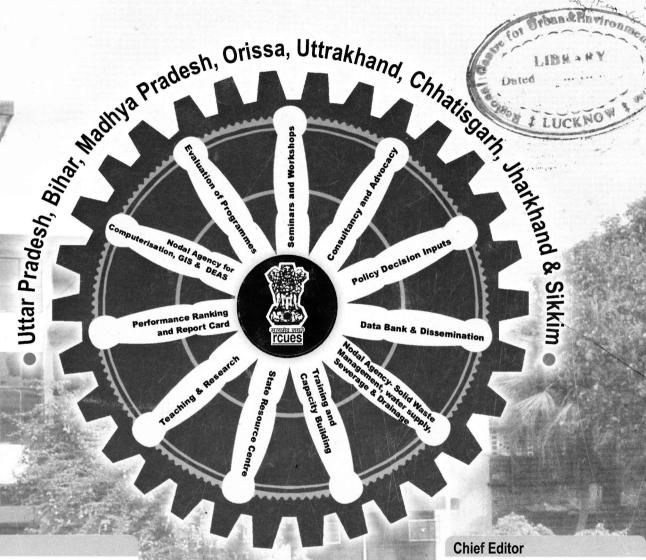
RCUES NEWSLETTER

(A Quarterly Publication)

VOL. III

January - March, 2007

No.4



INSIDE

- · News from Centre & States
- Faculty News
- · Forthcoming Activities
- Academic Calender

Prof. Nishith Rai (Director)

Editor

Dr. A.K. Singh (Asst. Director)

Editorial Assistance

Dr. R.K. Trivedi (Asst. Librarian)

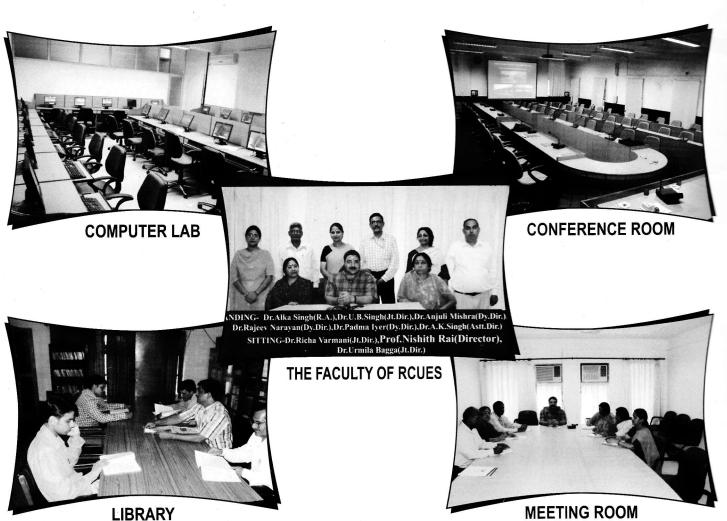
Regional Centre for Urban & Environmental Studies

(Established & Supported by the Ministry of Urban Development Govt. of India)

Adjacent Registrar's Office, University of Lucknow, Lucknow-226 007 (INDIA)







Please mail your correspondence to :

Prof. Nishith Rai

Director

Regional Centre For Urban & Environmental Studies

(Established by Ministry of Urban Development, Government of India)
Adjacent Registrar's Office, University of Lucknow, Lucknow-226 007 (INDIA)
Tel.: (0522) 2740165, 2740108, Fax: (0522) 2740165
e-mail: nkrai@hotmail.com, nkrai@rcueslko.ogr: Website: rcueslko.org



From the Chief Editor's Desk



प्रिय पाठकों.

व्यापक नगरीकरण 20 वीं सदी का परिदृश्य है। आज भारत की नगरीय आबादी 1900 में विश्व की कुल नगरीय आबादी से अधिक है। विश्व की लगभग आधी आबादी शहरों में रह रही है। अतः 21वीं सदी नगरीय सदी होगी। आज 'नगरों को विकास का इंजन' माना जाता है। एशिया में आर्थिक विकास की दर भी उच्च है और अनुमान है कि 2025 में भारत विश्व के 5 प्रमुख उपभोक्ता देशों में होगा तथापि नगरों में पर्यावरणीय गिरावट, नगरीय सेवाओं पर बढ़ता दबाव, अप्रवजन, जोखिमग्रस्त क्षेत्रों में जनसंख्या का बढ़ता घनत्व, अवस्थापना सुविधाओं की कमी तथा नगर निकायों की संसाधनहीनता आदि चुनौतियाँ उभरी हैं। इन चुनौतियों से निपटने हेतु शहरों को सक्षम बनाना अनिवार्य हो गया है। इस दिशा में भारत सरकार द्वारा नगरीय विकास योजनाएं –जे.एन.एन.यू.आर.एम., यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.,एन.यू.आई.एस. तथा आई. एच.एस.डी.पी. शहरों में अवस्थापना स्विधाओं के विकास हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से न केवल अवस्थापना स्विधाओं तथा आवासीय दशाओं में सुधार होगा बल्कि नगर निकायों में अनिवार्य व वैकल्पिक सुधारों को लागू करने से वे सशक्त होंगे। क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ बेहतर नगरीय शासन हेत् स्थानीय निकायों के क्षमता विकास एवं नगरीय क्षेत्र से जुड़े लोगों की क्षमता विकास के लिए सदैव प्रयासरत रहता है। भारत सरकार की नवीन योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद हमारे केन्द्र की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गयी है। केन्द्रं भारत सरकार एवं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परियोजना के तहत "विकेन्द्रीकृत नगरीय शासन की क्षमता विकास परियोजना" हेत् राज्य स्तरीय एजेन्सी के रूप में कार्यरत है, साथ ही दोहरी लेखा प्रणाली, भौगोलिक सूचना प्रणाली, ठोस कचरा प्रबंधन, रिपोर्ट कार्ड व्यवस्था आदि के प्रभावी क्रियान्वयन हेत् नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्यरत हैं। पाठकों एवं सभी स्थानीय निकायों से अनुरोध है कि अपने विचारों, नवप्रयासों एवं प्रबंधन से केन्द्र को अवगत कराते रहें जिससे इस 'न्यूज लेटर' के माध्यम से अन्य नगरीय निकाय, संस्थाएं एवं निर्वाचित प्रतिनिधि प्रेरित हो सकें।

> निश्रीधरार निशीथ राय निदेशक / मुख्य संपादक



From the Editor's Desk



Dr. A.K. Singh

Wide-spread urbanization is a 20th Century phenomenon. However, urbanization in India has been slow. Presently, highest rates of economic growth are being witnessed in Asian Countries, especially in India and China that have emerged as major economies of the globe. There has been decline in population growth in small and medium towns, whereas the larger cities are gradually swelling in terms of population density. This has created enormous stress on existing urban infrastructure and services. Thus, the task of urban infrastructure development is daunting challenge. It requires increased investment, public-private partnership and effective governance for delivering the public services to the urban dwellers. Urban reforms are imperative for strengthening various stakeholders engaged in urban development and governance. While the unfinished agenda of decentralization is yet to be accomplished. In this direction, centrally sponsored urban infrastructure development schemes - JNNURM, UIDSSMT and IHSDP are expected to contribute significantly in development and expansion of urban infrastructure and strengthening the delivery mechanism for providing municipal services.

Please intimate us the innovative efforts and experiences and the best practices in urban development and governance for publication in the News letter and their wider dissemination.

With best wishes.

Dr. A.K. SinghEditor

RCUES NEWS

UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश

Orientation Training Programme for Tax Assessment Officers, Tax Superintendents and Asstt. Tax Superintendents

During the past years, Tax Assessment Officers had been promoted in the urban local bodies in U.P. Also, Tax Superintendents and Assistant Tax Superintendents had been appointed, but they had never received any training so far. Hence there was a long felt need to orient them and to give them input on the various aspects of tax administration and management and the recent government policies in order to enhance their individual capacities.

The Regional Centre organized a 5 day's training programme during January 16 to 20, 2007 with the following main objectives:

कर निर्घारण अधिकारियों, कर अधीक्षकों तथा सहायक कर अधीक्षकों हेतु अभिमुखी प्रशिक्षण

पिछले वर्षों में प्रदेश के स्थानीय निकायों में कर निर्धारण अधिकारियों को प्रोन्नत किया गया है। साथ ही कर अधीक्षक तथा सहायक कर अधीक्षकों की भी नियुक्ति की गयी थी यद्यपि उन्हें कोई प्रशिक्षण नहीं मिला। अतः एक लम्बे समय से यह आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि उन्हें नगर विकास के विभिन्न आयामों, शासकीय योजनाओं, कर प्रशासन तथा प्रबंधन के विभिन्न पक्षों पर अभिमुख किया जाय जिससे कि उनकी क्षमता बढ़ सके।

इसी को ध्यान में रखकर 16 से 20 जनवरी, 2007 को एक पांच दिवसीय अभिमुखी प्रशिक्षण लखनऊ में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के निम्न



Participants with Mr. S. A. T. Rizvi, Chairman IIIrd S.F.C., Govt. of U.P, Prof. Nishith Rai, Director, faculty and Course Director Dr. Richa Varmani, Joint Director, RCUES.

- to make the officials aware of their duties and responsibilities
- to familiarize them with the various legislations relating to municipal tax administration, and
- to acquaint them with the working of urban local bodies, including the various aspects of financial management.

उददेश्य थे:-

- अधिकारियों को उनके अधिकारों तथा कर्तव्यों के बारे में जागरूक करनाः
- नगरीय वित्त प्रशासन से सम्बन्धित विभिन्न विधिक प्रावधानों के सम्बन्ध में प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान करना;
- प्रतिभागियों को शहरी स्थानीय निकायों की कार्य प्रणाली तथा वित्तीय प्रबंधन के विभिन्न

The focus areas of the Orientation were:

- Urban Development and Governance
- Financial Resources of Urban Local Bodies and the Need for their Mobilization
- Tax Management
- Municipal Budgeting and Accounting System
- · E-Governance in Financial Management
- Property Tax Reforms
- Role of Central and State Finance Commissions
- Disciplinary Enquiry and Service Rules
- · Team Building and Leadership

The training consisted of lecture-discussion sessions concentrating mainly on the above-mentioned topics concerned with municipal tax administration, its assessment and collection. The participants were also acquainted with the Urban Reforms Agenda of the Government of India, with special emphasis on the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) and its Sub-programmes. Prof. Nishith Rai, Director, RCUES welcomed the participants in the beginning of the course. The programme ended with a Panel Discussion Session which was presided over by Sri S.A.T. Rizvi, Chairman, IIIrd S.F.C., Government of U.P. The programme was attended by 26 officers of Nagar Nigams and Nagar Palika Parishads of the State of Uttar Pradesh. The guest faculty included Sri S.P. Singh, Special Secretary, Urban Development Department, Government of U.P., Sri A.K. Verma, former Director of Pensions, Government of U.P., Prof. J.L. Seth, Sri K.N. Srivastava, Consultant, IIIrd State Finance Commission, Government of U.P., Sri R.K. Gupta, UPDESCO, and Sri S.S. Srivastava, financial consultant.

The programme was directed by Dr. Richa Varmani, Joint Director, RCUES, Lucknow.

Orientation Training Programme for Revenue and Tax Inspectors

More than 200 Revenue and Tax Inspectors have been working in the urban local bodies of the State of Uttar Pradesh. However, they have not received any training so far. Hence there was a long-felt need to orient them and to give them proper training on the various aspects of urban administration and management and the recent government policies in order to enhance their individual capacities and augment the financial resources of the urban local bodies.

With a view to orienting the Revenue and Tax Inspectors working in the Nagar Nigams and Nagar

पक्षों के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करना; अभिमुखी प्रशिक्षण में प्रमुख विषय निम्न थे :—

- नगरीय विकास तथा प्रशासन;
- शहरी स्थानीय निकायों में वित्तीय संसाधन तथा उनको इकट्ठा करना
- कर प्रबंधन
- म्युनिसिपल बजट तथा एकाउंटिंग सिस्टम
- वित्तीय प्रबंधन में ई-प्रशासन
- सम्पत्ति कर सुधार
- केन्द्रीय तथा राज्य वित्त आयोगों की भूमिका
- अनुशासन, जॉच तथा सेवा नियम
- टीम निर्माण तथा नेतृत्व।

व्याख्यान तथा परिचर्चा आधारित सत्रों में उपरोक्त विषयों को विषय विशेषज्ञों द्वारा आच्छादित किया गया। प्रो. निशीथ राय, निदेशक ने कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। उन्होंने नगरीय विकास की नवीन योजनाओं के अंतर्गत लाभ लेने के लिए नगर निकायों में सुधार लागू करने के महत्व पर बल दिया। कार्यक्रम का अंत एक परिचर्चा के साथ हुआ। परिचर्चा की अध्यक्षता तृतीय राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एस. ए. टी. रिजवी ने की। इस कार्यक्रम में 26 कर निर्धारण अधिकारियों, कर अधीक्षकों तथा सहायक कर अधीक्षकों ने भाग लिया।

कार्यक्रम का संचालन डा० ऋचा वरमानी, संयुक्त निदेशक ने किया।

राजस्व तथा कर निरीक्षकों हेतु अभिमुखी प्रशिक्षण

उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों में लगभग 200 राजस्व तथा कर निरीक्षक कार्यरत हैं तथापि उन्होंने कोई प्रशिक्षण भी प्राप्त नहीं किया है। अतः एक लम्बे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि उन्हें नगरीय विकास तथा प्रबंधन से सम्बंधित विभिन्न पक्षों, आयामों तथा नीतियों के सम्बन्ध में अभिमुख किया जाय, जिससे कि उनकी कार्य क्षमता बढ़ सके और वे स्थानीय निकायों में वित्तीय संसाधन बढ़ा सकें। इसी का ध्यान में रखकर केन्द्र ने नगर निगमों तथा नगर



Participants with Mr. S.A.T. Rizvi (Chairman, Illrd State Finance Commision of UP, Mr. A.K. Gupta, Chief Engineer, Local Bodies, Govt. of U.P. faculty and Course Director Dr. Richa Varmani, Joint Director,

Palika Parishads of U.P., a five-days' orientation training programme was organized from February 20-24, 2007 with the following main objectives:

- to make the officials aware of their duties and responsibilities
- to familiarize them with the various legislations relating to municipal tax administration, and
- to acquaint them with the working of urban local bodies, specially detailed aspects of financial management.

The focus areas of the orientation were:

- Urban Development and Governance
- Financial Resources of Urban Local Bodies and the Need for their Mobilization
- Tax Management
- Municipal Budgeting, Accounting and Auditing
- E-Governance in Financial Management
- Property Tax Reforms
- Role of Central and State Finance Commissions
- Disciplinary Enquiry and Service Rules
- · Team Building and Leadership

The training consisted of lecture-discussion sessions concentrating mainly on the above-mentioned topics concerned with urban administration as well as its assessment and collection. The participants were also acquainted with the Urban Reforms Agenda of the Government of India, with special emphasis on the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) and its Sub-programmes.

पालिका परिषदों के राजस्व तथा कर निरीक्षकों हेतु एक पांच दिवसीय अभिमुखी प्रशिक्षण 20 से 24 फरवरी, 2007 तक आयोजित किया। इस कार्यक्रम के निम्न उद्देश्य थे:

- अधिकारियों को उनके कर्तव्यों तथा अधिकारों के संबंध में जागरूक करना;
- नगरीय प्रशासन से संबंधित विभिन्न विधायी उपबन्धों के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करना;
- वित्तीय प्रबंधन में स्थानीय निकायों की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में जानकारी देना।

कार्यक्रम में निम्न विषय शामिल किए गये:

- शहरी विकास तथा शासन
- स्थानीय निकायों में वित्तीय संसाधन तथा उनका एकत्रीकरण
- कर प्रबंधन
- बजट तथा एकाउंटिंग सिस्टम
- सम्पति कर सुधार
- केन्द्र तथा राज्य वित्त आयोगों की भूमिका
- अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा सेवा नियम
- समूह निर्माण तथा नेतृत्व।

व्याख्यान तथा परिचर्चा आधारित सत्रों में विषय

Prof. Nishith Rai, Director, RCUES welcomed the participants in the beginning of the course. Sri S.P. Singh, Special Secretary, Urban Development Department, Government of Uttar Pradesh inaugurated the training programme and delivered his inaugural lecture on "Urban Development and Governance". The Programme ended with a Panel Discussion Session which was presided over by Sri S.A.T. Rizvi and had Prof. Nishith Rai and Dr. Richa Varmani as members. Sri S.A.T. Rizvi, Chairman, Illrd S.F.C., Government of U.P. was the Chief Guest at the Valedictory Session who distributed the certificates to the participants. The programme was attended by 11Revenue Officers and Tax Inspectors from the Nagar Nigams and Nagar Panchayats of the State of Uttar Pradesh.

The Orientation Training Programme was directed by Dr. Richa Varmani, Joint Director of the RCUES.

विशेषज्ञों ने उपरोक्त वर्णित विषयों को विभिन्न सत्रों में आच्छादित किया। कार्यक्रम का उद्घाटन श्री एस. पी. सिंह, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ने किया। कार्यक्रम का अंत एक परिचर्चा के साथ हुआ जिसमें तृतीय राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एस. ए. टी. रिजवी ने प्रतिभागियों को सम्बोधित किया। इस कार्यक्रम में 11 राजस्व तथा कर निरीक्षकों ने भाग लिया।

कार्यक्रम का संचालन डा. ऋचा वरमानी, संयुक्त निदेशक ने किया।

Orientation Training Programme for Newly Appointed Executive Officers of Uttar Pradesh

During the past years, Executive Officers had been appointed to the urban local bodies of the state of Uttar Pradesh but they had not received any training on urban government. Therefore, there was a long felt need to orient them and to give them input on the various aspects of urban administration and management and the recent government policies in order to enhance their individual capacities. With a view to orienting the Executive Officers of the state of Uttar Pradesh a ten days training was organized with the following main objectives:

- to make the officials aware of their duties and responsibilities
- to familiarize them with the various legislations relating to municipal tax administration, and

नव नियुक्त अधिशासी अधिकारियों हेतुअभिमुखी प्रशिक्षण

उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों में पिछले वर्षों में अधिशासी अधिकारियों की नियुक्तियाँ हुई हैं परन्तु उन्हें नगरीय शासन के सम्बन्ध में प्रशिक्षण नहीं दिया गया। अतः एक लम्बे समय से आवश्यकता प्रतीत हो रही थी कि उन्हें नगरीय प्रशासन तथा प्रबंधन से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं, पक्षों तथा नीतियों पर जानकारी दी जाए जिससे कि उनकी व्यक्तिगत क्षमता बढ़ सके। इन्हीं बिन्दुओं को ध्यान में रखकर केन्द्र ने एक दस दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन 8 से 17 मार्च, 2007 को लखनऊ में किया। इस कार्यक्रम के निम्न उददेश्य थे:—



Participants with Mr. Amal Kumar Verma, Principal Secretary, Urban Development, Govt. of U.P, Prof. Nishith Rai, Director, faculty and Course Director Dr. Richa Varmani, Joint Director, RCUES

 to acquaint them with the working of urban local bodies, including the various aspects of financial management.

The focus areas of the orientation were:

- salient features of 74th Constitution Amendment Act
- financial resources of urban local bodies and the need for their mobilization;
- tax management;
- · municipal budgeting, accounting and auditing;
- · management of urban services;
- · office management;
- · urban poverty alleviation programmes;
- Public Private-Partnership and Community Participation
- disciplinary enquiry and service rules

The training consisted of lecture-discussion mainly on the above mentioned topics concerned with urban administration and governance. The participants were also acquainted with the urban reforms agenda with special emphasis on JNNURM and its subprogrammes. The participants were also given practical training on application of computers in the computer lab of the Centre. They also visited the Directorate of Local Bodies, Government of U.P. and were familiarized with its web site and the method to e-mail their relevant reports and data to the Directorate. The participants also attended a one-day workshop on Preparation of Detailed Project Reports (on water supply and sewerage projects, storm water drainage, waste management, roads/highways projects and public transport etc. under JNNURM scheme) supported by the Ministry of Urban Development, Government of India on 16th March, 2007.

The programme was inaugurated by Sri Amal Kumar Verma, Principal Secretary, Department of Urban Development, Government of U.P. while Sri Anil Kumar Sagar, Director, Urban Local Bodies, addressed the participants at the closing function. The programme was attended by 19 newly appointed Executive Officers of Nagar Panchayats of the state.

The Programme was directed by Dr. Richa Varmani, Joint Director, RCUES, Lucknow.

- अधिकारियों को उनके कर्तव्यों तथा अधिकारों के सम्बन्ध में जागरूक करना;
- नगरीय प्रबंधन से सम्बन्धित विधिक प्राविधानों की जानकारी प्रदान करना;
- स्थानीय निकायों की कार्य प्रणाली तथा वित्तीय प्रबंधन व प्रशासन की जानकारी प्रदान करना।

इस कार्यक्रम के निम्न विषय प्रमुख थे :--

- 74वें संवैधानिक संशोधन की प्रमुख विशेषतायें
- स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधन तथा उनके दोहन की आवश्यकता
- कर प्रबंधन
- म्युनिसिपल एक्ट, लेखा तथा लेखा परीक्षण
- नगरीय सेवाओं का प्रबंधन
- कार्यालय प्रबंधन
- नगरीय निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम
- सार्वजनिक—निजी भागीदारी तथा सामुदायिक सहभागिता
- अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा सेवा नियम।

व्याख्यान तथा परिचर्चा आधारित विभिन्न सत्रों में विषय विशेषज्ञों ने उपरोक्त विषय आच्छादित किए गये। श्री अमल कुमार वर्मा, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ. प्र. शासन ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया जबिक कार्यक्रम के समापन सत्र में श्री अनिल कुमार सागर, निदेशक, स्थानीय निकाय, उ. प्र. ने प्रतिभागियों को सम्बोधित किया। इस कार्यक्रम में 19 नव नियुक्त अधिशासी अधिकारियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम का संचालन डा. ऋचा वरमानी, संयुक्त निदेशक ने किया।

Training Programmes Role of Urban Local Bodies In Disaster Management

India is one of the major theatres of disasters both natural and human made. Uttar Pradesh has witnessed various kinds of disasters and its consequences over the period. The increasing risk factors of disasters in urban areas have caused concern for policy makers and also local governments. In the State, 13 districts fall under 125 most vulnerable districts of India while UNDP-India Programme on Disaster Risk Management has covered 19 districts of the state. Constitutional Amendments (73rd and 74th) in 1992 gave the status of institutions of self government to local bodies and the scope for urban local governments in disaster mitigation and management has widened in the context of decentralized governance. Keeping the importance of strengthening the capacity of urban local bodies in disaster management, the Regional Centre organized a two day training programme on Role of Urban Local Bodies in Disaster Management on February 26th-27th, 2007. In the programme 36 officials of urban local bodies and jal sansthans participated. The programme objectives were as follows:

- to review the status, situation, dimensions and trends of disasters and their impact on development;
- to examine role of government agencies in disaster mitigation and response;
- to examine the role of local self governments in disaster mitigation and response;
- to examine the role of NGO's, civil societies and other stakeholders in disaster management;
- to discuss legal and policy framework of disaster management;
- to orient officials regarding planning for prevention and response of disasters as well as rehabilitation and reconstruction of disaster affected victims and areas;
- to suggest measures for mitigating disasters
 The programme through lecture discussion sessions focussed on legal and policy

आपदा प्रबंधन में स्थानीय निकायों की भूमिका विषयक प्रशिक्षण कार्यकम

भारत में प्राकृतिक तथा मानव जनित आपदाएं निरन्तर घटती रहती हैं। इनमें बाढ, सुखा, चक्रवात, भूकम्प, साम्प्रदायिक दंगे, आगजनी आदि प्रमुख हैं। आपदाओं के कारण वर्षों की सामाजिक-आर्थिक प्रगति बर्बाद हो जाती है। नगरीकरण, जोखिमयुक्त स्थानों में घरों का बढता घनत्व तथा आबादी का संकेन्द्रण तथा गैर इंजीनियरिंग भवनों के निर्माण से शहरों में जोखिम बढ़ रहा है। भारत सरकार के 125 जनपदों की अत्यधिक जोखिमयुक्त जनपदों के रूप में पहचान की है और इन जनपदों में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रायोजित आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम चलाया है। प्रदेश के 19 जनपदों में इस तरह का कार्यक्रम भी संचालित है। विकेन्द्रीकरण के संदर्भ में स्थानीय निकायों की भूमिका बढी है और आपदा प्रबन्धन में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका तलाश की जा रही है। इन्हीं बिन्दुओं को ध्यान में रखकर एक दो दिवसीय अभिमुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन केन्द्र ने 26 व 27 फरवरी, 2007 को लखनऊ में किया। इस कार्यक्रम के निम्न उददेश्य थे:-

- आपदाओं के विभिन्न आयामों, प्रवृत्तियों, स्थिति तथा विकास पर उनके प्रभाव की समीक्षा करना;
- आपदा को न्यून करने तथा प्रतिउत्तर हेतु सरकारी अभिकरण इकाईयों की भूमिका की जॉच करना;
- आपदा को न्यून करने तथा उनके प्रतिउत्तर में स्थानीय निकायों की भूमिका का परीक्षण करना;
- आपदा प्रबन्धन में स्वैच्छिक संस्थाओं तथा अन्य समुदाय आधारित संगठनों की भूमिका का परीक्षण करनाः
- आपदा प्रबंधन के विधिक तथा नीतिगत ढांचे पर विचार करना;
- आपदा प्रबंधन नियोजन हेतु बचाव, प्रतिउत्तर, पुनर्वासन तथा पुनर्सरचना के सम्बन्ध में प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान करना;
- आपदा प्रबंधन हेतु उपायों को सुझाना।

framework, planning for prevention, response, mitigation and rehabilitation and reconstruction of disasters affected persons and areas. The training programme was inaugurated by Prof. Nishith Rai, Director of the Centre. He stressed on the need of strengthening urban local bodies for their active role in disaster management. In the valedictory session, Sri Amal Kumar Verma, Principal Secretary, Department of Urban Development, Government of Uttar Pradesh, Lucknow addressed the participants. He said that urban local bodies are to be strengthened through capacity building in disaster management in order to make them efficient in taking active role in disaster management in their respective areas.

The programme was jointly directed by Dr. U.B. Singh, Joint Director and Dr. A.K. Singh, Assistant Director.

Training Programme on Report Card System

Report Card System is a strategic tool developed to help citizens provide feed back and engage sate agencies in order to improve service delivery and governance. The system is an effective tool and is useful in evaluating various aspects like people's participation, rule of law, transparency, responsiveness, equity, effectiveness and efficiency, accountability and strategic vision etc. Studies have, been undertaken by various bodies to establish and monitor public opinion with respect to the delivering public services. Report Cards are a method of measuring public opinion in a structured way. The Report Card System attempts to assess, rank and benchmark the following parameters: i) overall satisfaction with service delivery (levels of services), ii) the extent and coverage of services; iii) patterns of emerging problems;' iv) the responsive of agencies to reported problems and grievances; v) the effectiveness of bribes in rectifying reported problems. In the state of Uttar Pradesh, Report Card System was introduced on a pilot basis under UNDP assisted project on Capacity Development for Urban Governance. The system has become a regular

प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन के विधिक, नीतिगत ढांचे, बचाव तथा न्यूनीकरण, प्रतिउत्तर, पुनर्वासन तथा पुनर्संरचना व समुदाय आधारित संगठनों की भूमिका आदि विषयक बिन्दुओं पर व्याख्यान तथा परिचर्चा आधारित सत्रों में विषय विशेषज्ञों ने जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रो.निशीथ राय, निदेशक ने किया। कार्यक्रम के समापन सत्र में श्री अमल कुमार वर्मा, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ. प्र. शासन ने प्रतिभागियों को सम्बोधित किया। उन्होंने आपदा प्रबन्धन में स्थानीय निकायों को मजबूत करने हेतु क्षमता संवर्धन पर बल दिया। कार्यक्रम में उ. प्र.नगर निकायों के 36 अधिशासी अधिकारी, सहायक अधिशासी अधिकारी तथा जल संस्थानों के अभियंता भी शामिल हुए।

कार्यक्रम का संचालन डा. यू. बी. सिंह, संयुक्त निदेशक तथा डा. अवधेश कुमार सिंह, सहायक निदेशक ने संयुक्त रूप से किया।

रिपोर्ट कार्ड सिस्टम पर प्रशिक्षण कार्यकम

भारत ने शहरी सेवाओं के लिए व्यापक बाह्य संरचना की स्थापना में निश्चित सफलता प्राप्त की है, लेकिन यह उपलब्धि शायद सेवाओं अथवा सामाजिक दायित्व के समवर्ती उच्च स्तरों से मेल नहीं रखती। समस्या निवेश की नहीं, अपित्र शासन की गुणवत्ता तथा आम नागरिक को राज्य द्वारा व्यवस्थित सेवा उपलब्ध कराने वालों की प्राथमिकताओं और कार्यक्रमों को प्रभावित करने की क्षमता की है। सार्वजनिक सेवाओं का रिपोर्ट कार्ड, पब्लिक अफेयर्स सेन्टर, बंगलौर में एक लाभ रहित संस्थान द्वारा नागरिकों को सीधे लाभ पहुँचाने तथा बेहतर सेवाएं देने में जुटी राज्य एजेन्सियों को शासन की मदद हेत तैयार करने के लिए विकसित किया गया जो कि एक निर्णायक उपाय है। इसी परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, द्वारा एक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम-रिपोर्ट कार्ड सिस्टम विषय पर उत्तर प्रदेश की नगर निकायों में कार्यरत सहायक नगर आयुक्तों एवं अधिशासी अधिकारियों हेतु फरवरी 7-9, 2007 को लखनऊ में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के निम्न उददेश्य थे

feature in the state. The RCUES has already conducted Report Card Survey in 51 class I towns of U.P. In order to implement Report Card System effectively in the Urban Local Bodies, a three day's training programme on Report Card System was organized from Februrary 7-9, 2007 by RCUES, Lucknow.

The training programme had the following main objectives:

- to discuss concept, need, and importance of Report Card System
- to discuss the planning strategy, process and method of Report Card System being implemented
- to make acquaint with various aspects of Report Card System and its advantages

The focus of training programme was on conceptualization, need and importance of Report Card System; planning strategy, process and method, findings of Report Card System, ranking achieved by different towns and experience sharing. programme through lecture-discussion sessions focused on above mentioned topics. In the programme 25 Assistant Municipal Commissioners and Executive Officers of various local bodies of U.P. participated. The guest faculty included Sri R.K. Chaturvedi, Director (UD), Ministry of Urban Development, Government of India, Sri Subhash Chandra, Under Secretary, Ministry of Urban Development, Government of India, Dr. S.C. Rai, Former Mayor, Lucknow Municipal Corporation, Lucknow, and Sri S.K. Mishra, Chief Finance and Account Officer, Directorate of Urban Local Bodies, Government of U.P. Shri R.K. Chaturvedi in his valedictory address highlighted the need and importance of Report Card System in municipal urban services.

- प्रतिभागियों को रिपोर्ट कार्ड सिस्टम की आवश्यकता एवं महत्व से परिचित कराना;
- प्रतिभागियों को रिपोर्ट कार्ड सिस्टम के प्रमुख अवयव, सर्वे प्रक्रिया एवं लाभ से परिचित कराना;

प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की गयी:

- रिपोर्ट कार्ड सिस्टम की आवश्यकता, महत्व एवं अवधारणाः
- रिपोर्ट कार्ड हेतु आंकड़ा संग्रह, प्रश्नावली का निर्माण एवं आंकड़ा विश्लेषण;
- रिपोर्ट कार्ड तैयार करना:
- रिपोर्ट कार्ड के अभिनव अनुभव।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषदों के 25 सहायक नगर आयुक्तों एवं अधिशासी अधिकारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्णतः व्याख्यान एवं चर्चा पद्धति पर आधारित था। प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्री आर. के. चतुर्वेदी, निदेशक (नगर विकास), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, श्री सुभाष चन्द्रा, अनु सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पदमश्री डा. एस. सी. राय, पूर्व महापौर, लखनऊ नगर निगम, लखनऊ एवं श्री एस. के. मिश्रा, मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन ने भी सम्बोधित किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन सत्र में श्री आर. के. चतुर्वेदी ने कहा कि रिपोर्ट कार्ड नागरिकों का विश्वसनीय एवं वृहत प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होते हैं। इसे सफल बनाने के लिए स्थानीय निकायों को अपना आधारभूत



Participants with Dr. S.C.Rai, former Mayor, LMC with faculty and Course Director Dr. Anjuli Mishra, Deputy Director

The programme was directed by Dr. Anjuli Mishra, Deputy Director, RCUES, Lucknow.

संरचना के दायरे को बढ़ाना होगा। कार्यक्रम का संचालन डा. अंजुली मिश्रा, उप निदेशक ने किया।

Training Workshop for Newly Elected Chairpersons of Class I Cities of U.P.

The third election of urban local bodies in U.P. has been recently completed. It is imperative to orient the elected representatives of urban local bodies about urban development, and governance. A two day orientation programme for newly elected chairpersons of Nagar Palika Parishads of U.P. was organized by RCUES, Lucknow from January 5-6, 2007 at Lucknow with the aims of orienting the chairpersons regarding urbanization and its implications on urban development, their role and responsibilities in city development and challenges of governance and effective

नवनिर्वाचित अध्यक्षों हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला

प्रदेश में तीसरा चुनाव अभी हाल में ही सम्पन्न हुआ है। नगर विकास के बदलते परिप्रेक्ष्य में समस्त नव निर्वाचित महापौरों, नगर अध्यक्षों एवं सदस्यों को नगर प्रशासन के विभिन्न आयामों से अभिमुख कराना अनिवार्य है। इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश की प्रथम श्रेणी के नगर पालिका परिषदों के नव निर्वाचित अध्यक्षों हेतु एक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन केन्द्र ने 5–6 जनवरी, 2007 को लखनऊ में किया। इस कार्यक्रम के निम्न उददेश्य थे:

- नगरीकरण के प्रभाव तथा नगरीय परिदृश्य में हो रहे परिवर्तनों पर प्रकाश डालना;
- भारत में नगर प्रशासन का उद्भव एवं विकास;
- संविधान के 74वें संशोधन, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के प्राविधानों से अवगत कराना;
- पालिका के आय के स्रोत, स्रोतों के दोहन, नये स्रोतों की तलाश एवं करारोपण एवं करों की वसूली को प्रभावी बनाने के उपाय सुझाना;
- नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता एवं दक्षता बढ़ाने में सामुदायिक सहभागिता एवं निजी क्षेत्र को आकर्षित करने के मार्ग तलाशना



implementation of development programmes and schemes. The lecture-discussion sessions focused on urbanization and its implications, origin, growth and development of urban administration, provisions of 74th Constitutional Amendment Act, Provisions of Nagar Palika Act, 1916, functions, finances, resources mobilization in urban local bodies, management of services; development schemes and programmes, public-private partnership etc.

The programme was inaugurated by Hon'ble Minister, Urban Development Development, Government of U.P. Sri Md. Azam Khan. He lamented over the poor financial status of urban local bodies in the state. He said that urban local

- पालिका प्रशासन को बेहतर जवाबदेह, प्रभावी एवं समुदायोन्मुख बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालना;
- नगर विकास के विभिन्न कार्यक्रमों यथा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जे. एन. एन. यू. आर. एम.यू. आई. डी.एस.एस.एम.टी.,आई.एच.एस.डी.पी. योजनाओं से परिचित कराना;
- नवनिर्वाचित नगर अध्यक्षों को उनके कर्तव्य, उत्तरदायित्व, शक्तियों एवं प्राधिकारों से परिचित कराना;
- नगर नियोजन में समुदाय एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका के महत्व पर प्रकाश डालना;
- निर्वाचित नगराध्यक्षों की समस्याओं के समाधान तलाशना;
- देश के दूसरे राज्यों में किए जा रहे सुशासन के अच्छे प्रयासों से परिचित कराना।

प्रशिक्षण में निम्न विषय आच्छादित किए गये:

- उत्तर प्रदेश में बढ़ते नगरीकरण का प्रभाव एवं उससे उत्पन्न समस्यायें;
- भारत में पालिका प्रशासन का उद्भव एवं विकास
 एक सिंहावलोकन;
- संविधान के 74वें संशोधन के प्राविधान:

bodies in the state are not in a position to mobilise their share of 10 per cent in centrally sponsored urban development schemes. He remarked that there was no need to develop large cities beause they would attract more migration from rural to urban areas, as well from smaller cities to larger cities. Earlier, Prof. Nishith Rai, Director, RCUES, Lucknow said that the urban local bodies in the state were in a precarious financial condition. The lecturediscussion sessions focused on various dimensions and aspects of urban development, governance and functioning of development schemes, programmes and projects. The guest speakers included Sri Amal Kumar Verma, Principal Secretary, Department of Urban Dvelopment, Government of U.P., Sri R.K. Mittal, Divisional Commissioner, Lucknow, Sri Anil Kumar Sagar, Director, Directorate of Urban Local Bodies, Lucknow, Sri S.P. Singh, Special Secretary, Department of Urban Development, Government of U.P. Besides internal faculty taught on various topics. In the valedictory session, Sri Amal Kumar Verma, Principal Secretary, Department of Urban Development, Government of U.P. and Sri Anil Kumar Sagar, Director, Directorate of Urban Local Bodies, Government of U.P. participated in panel discussion. Sri Verma highlighted on the need of enhancing the scope of public private partnership, imposing user charges, widening the domain of house tax, and computerization while Sri Sagar called for completing the unfinished agenda of decentralization in the state. Sri R.K. Mittal, Divisional Commissioner, Lucknow stressed on the need of widening the scope of community based organizations in development. In the programme 20

- उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 का परिचय ;
- नगरीय क्षेत्र में लागू होने वाले अन्य कानूनों तथा कार्य करने वाले अन्य अभिकरणों का विवरण;
- उत्तर प्रदेश में पालिकाओं के कृत्य ;
- उत्तर प्रदेश में पालिकाओं की आय के कर एवं करेतर स्रोतों पर प्रकाश. नये स्रोतों की तलाश आदि;
- पालिकाओं द्वारा करों, शुल्कों आदि का आरोपण एवं वस्ली;
- सम्पत्ति कर (भवन कर) के आरोपण हेतु मूल्यांकन, कर निर्धारण, किमयों एवं सुधार पर चर्चा;
- राज्य वित्त आयोग तथा केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चाः
- जिला नियोजन समिति, महानगर नियोजन समिति एवं नगर नियोजन के अन्य आयामों का परिचय;
- नागरिक सेवाओं यथा जलापूर्ति, सीवर, नाली, सड़क, ठोस कूड़ा प्रबंधन आदि की प्रभावी उपलब्धता;
- कर समितियों, एरिया सभा आदि से परिचित कराना
- फेरी नीति, आवास नीति, नगर विकास नीति आदि पर चर्चा;
- नगर विकास के कार्यक्रम यथा एस. जे. एस. आर. वाई.,
 जे. एन. एन.यू. आर. एम., यू. आई. डी. एस. एस. एम.टी.
 तथा आइ. एस. एच. डी.पी. आदि पर चर्चा;
- नगरीय सुधारों के महत्व पर प्रकाश;
- निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकार एवं कर्तव्य तथा नगर प्रशासन में उनकी भूमिका;
- पालिका की बैठकों की कार्यवाही की प्रकिया;
- नगर विकास में जन सहभागिता बढ़ाने एवं निजी क्षेत्र को जोड़ने में निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका;
- 21वीं सदी में नगर प्रशासन की चुनौतियाँ कुछ उभरते मददे

कार्यक्रम में भाग लेने हेतू उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के प्रथम श्रेणी के नगरों की नगर पालिका परिषदों में कुल 39 अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया था जिसमें से 20 अध्यक्षों ने प्रतिभाग लिया। कार्यक्रम का उदघाटन श्री मोहम्मद आजम खाँ, माननीय मंत्री, संसदीय कार्य, जलापूर्ति, नगर विकास तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। अपने उदघाटन भाषण में श्री खॉ ने नव निर्वाचित पालिका अध्यक्षों को सदन की बैठक नियमित बुलाने तथा उसके संयमित संचालन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि योजनाएं ऐसी बनायी जानी चाहिए कि उनका क्रियान्वयन आसानी से किया जा सके। कार्यशाला का समापन एक परिचर्चा के साथ हुआ जिसमें उत्तर प्रदेश में नगर विकास की चुनौतियों के ऊपर विचार विमर्श किया गया। परिचर्चा की अध्यक्षता श्री अमल कुमार वर्मा, प्रमुख सचिव, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, उ. प्र.शासन ने किया। अपने सम्बोधन में श्री वर्मा ने नव निर्वाचित अध्यक्षों को आदर्श जनपद योजना तथा त्वरित आर्थिक विकास योजना का महत्तम लाभ उठाने की सलाह दी। उन्होंने निजी क्षेत्र की सहभागिता बढ़ाने, उपयोगिता शुल्क लगाने, गृहकर का दायरा बढ़ाने, कम्प्यूटरीकरण कराने आदि पर जोर दिया। परिचर्चा के विशिष्ट अतिथि श्री अनिल कुमार सागर, निदेशक, स्थानीय निकाय ने कहा कि 74वें chairpersons attended against the 39 invited chairpersons.

The programme was directed by Dr. U.B. Singh, Joint Director, RCUES, Lucknow.

संविधान के परिप्रेक्ष्य मे निकाय पूर्ण विकेन्द्रीकरण के लिए कृत संकल्प हैं। परिचर्चा में भाग ले रहे श्री आर. के. मित्तल, मण्डलायुक्त, लखनऊ ने कहा कि नगर विकास हेतु विकेन्द्रीकरण ही एक विकल्प है।

कार्यक्रम का नेतृत्व व संचालन डा. यू. बी. सिंह, संयुक्त निदेशक ने किया।

BIHAR

Three Training Workshops for Elected Women Councillors of Urban Local Bodies

Government of India has initiated a special scheme for Capacity Building of Women Councilors through residential training on different aspects of urban development and governance. The training components include origin, growth and development schemes, programmes and policies - UIDSSMT, IHSDP, JNNURM, SJSRY; rights and duties of women councilors; municipal resources and financial management; disaster management; management of urban services, etc. The programmes were conducted under the joint

बिहार

निर्वाचित महिला पार्षदों के लिए तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम

समाज के विकास में महिलाओं की अहम भूमिका है। संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण मिलने से महिलाओं को निर्माण प्रक्रिया में सक्रिय योगदान देने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने की दृष्टि से महिला पार्षदों को क्षमता विकास के अवसर उपलब्ध कराने हेतु बिहार राज्य ने नितांत आवश्यक समझा। अंतिम चरण में बिहार राज्य की नगर निकायों की निर्वाचित महिला पार्षदों हेतु तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन केन्द्र ने पटना में 12 से 14फरवरी, 15 से 17 फरवरी तथा 19 से 21फरवरी, 2007 को किया। इन प्रशिक्षण कायक्रमों के निम्न उद्देश्य थे:



aspices of Government of India and state government.

The Regional Centre organized a series of training workshops for the benefit of elected women councillors of the state. Accordingly, three training workshops were organized at Hotal Patliputra Ashok, Patna for elected women representatives of Nagar Panchayats from February 12 to 14, 15 to 17 and 19 to 21, 2007respectively. In the first programme, 11 women councillors, while in second and third programme 10 and 16 women representatives participated. The programmes were inaugurated by Shri Sugandh Chaturvedi, Deputy Director, Department of Urban Development, Government of Bihar. stressed on implementing urban reforms and capacity building of local bodies. In the third programme, on 19th February 2007, Sri R.K. Chaturvedi, Director (UD), Ministry of Urban Development, Government of India, Delhi, Sri. M.L. Choutani, Town and Country Planning Organization, Government of India, Delhi and Dr. N. Safeena, Special Secretary, Department of Urban Development, Government of Bihar also addressed the participants. Sri Chaturvedi called for improving financial status of urban local bodies through introducing reforms. Sri Choutani said that community based organizations need to be strengthened in the context of decentralized governance. Safeena emphasized on introducing Municipal Cadre and training for officials, employees and representatives of local bodies.

The programmes were directed by Dr. A.K. Singh, Assistant Director.

- निर्वाचित महिला सदस्यों को अधिनियमों के प्राविधानों से परिचित करानाः
- महिला सदस्यों के अधिकारों एवं कर्तव्य पर प्रकाश डालना;
- बोर्ड की बैठकों में भाग लेने तथा प्रश्न पूँछने की प्रक्रिया से परिचित कराना;
- पालिका के आय के स्रोतों पर प्रकाश डालना तथा उनके दोहन के उपाय सुझाना;
- पालिका के बजट निर्माण में निर्वाचित सदस्यों की भूमिका से परिचित कराना;
- नगर विकास के कार्यों में निजी क्षेत्र तथा समुदाय की सहभागिता प्राप्त करना और विकास कार्यों तथा सेवा प्रदायता में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालना;
- महिला सदस्यों की दोहरी भूमिका में उठने वाली कठिनाइयों का पता लगाना तथा उन्हें दूर करने के उपाय सुझाना;
- नगर विकास के विभिन्न कार्यक्रमों (जे.एन.एन.यू.आर. एम.,यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. तथा आई.एच.एस.डी. पी) की जानकारी देना।

उपरोक्त उददेश्यों को ध्यान में रखकर पूरी अवधि को विभिन्न सत्रों में विभाजित किया गया। प्रत्येक सत्र हेत् एक विशिष्ट विषय आवंटित किया गया। जिस पर विस्तार से वक्ताओं ने परिचर्चा तथा व्याख्यान के माध्यम से प्रकाश डाला। तीनों कार्यक्रमों का उद्घाटन बिहार राज्य के नगर विकास विभाग के उप निदेशक श्री सुगंध चतुर्वेदी ने किया। तीसरे कायक्रम में (19फरवरी,2007) शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशक श्री आर. के. चतुर्वेदी, नगर नियोजक, ग्राम्य एवं नगर नियोजन, भारत सरकार के श्री एम. एल. चौटानी तथा विशेष सचिव, नगर विकास, बिहार सरकार के डा. एन. सफीना ने प्रतिभागियों को सम्बोधित किया। श्री चतुर्वेदी ने स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को सदढ करने हेतू सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया और राज्य सरकार से अपेक्षा की कि स्थानीय निकायों को जनसंख्या के अनुपात में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये। चौटानी ने विकेन्द्रीकृत नियोजन हेतू सामुदायिक संगठनों को सशक्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया जबिक डा.सफीना ने राज्य में म्युनिसिपल कैडर स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम में क्रमशः 11, 10 तथा 16 महिला पार्षदों ने भाग लिया।

कार्यक्रमों का संचालन डा. अवधेश कुमार सिंह, सहायक निदेशक ने किया। Basic services for urban poor. For rest of cities/towns of the country, two schemes namely UIDSSMT and IHSDP have been implemented. The Regional Centre organized three one day workshops at Khandwa and Ujjain, Madhya Pradesh from February 21, 22 and 24, 2007. In the first workshop, officials of different local bodies were present while in the second workshop representation of Chairman, Deputy Chairman, Councillors, Members of MIC/PIC representatives of MLA was ensured. The objectives of the workshops were:

- to sensitize the participants about the schemes and programmes of Government of India.
- to acquaint the participants with components of UIDSSMT and IHSDP, reforms agenda and provisions of central assistance;
- to discuss the role and duties of elected representatives in implementation of the schemes.

The programme through lecture-discussion sessions focussed on different aspects and dimensions of UIDSSMT and IHSDP. The first programme was inaugurated by District Magistrate, Khandwa, Sri Nikuni Srivastava while the second programme was inaugurated by Sri Veer Singh Hindon, Mayor, Khandwa Nagar Palika Nigam. In these programmes Sri Somnath Jharia, Municipal Commissioner, Khandwa and Sri Vivek Singh, Deputy Collector, Khandwa were also present. In the first programme 35 officials and in the second programme, 42 participants attended the workshop. In the third workshop organized at Uijain 29 officers and members of MIC participated.

The programmes were directed by Dr. Urmila Bagga, Joint Director, RCUES, Lucknow.

शहरों के अलावा देश के अन्य नगरों / शहरों में अवस्थापनाओं में समृचित सुधार लाने के उद्देश्य से शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अर्बन इफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमैंट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स (य.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) तथा इन्ट्रीग्रेटेड हाउसिंग एण्ड स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम (आई.एच.एस.डी.पी.) आरम्भ की हैं। इन योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने हेत् केन्द्र ने तीन एक दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन मध्य प्रदेश के खंडवा प्रथम कार्यशाला का तथा उज्जैन में किया। आयोजन २१फरवरी, २००७ को खण्डवा में किया गया जबकि दसरा कार्यक्रम भी 22 फरवरी, 2007 को खंडवा में ही आयोजित किया गया। तीसरा कार्यक्रम 24 फरवरी, 2007 को उज्जैन में आयोजित किया गया।

कार्यशालाओं के निम्न उद्देश्य थे:

- प्रतिभागियों को भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली दोनों नवीन योजनाओं के बारे में संवेदीकृत करना;
- योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु अनिवार्यताओं से प्रतिभागियों को परिचित कराना;
- योजनाओं के क्रियान्वयन में निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की भूमिका एवं दायित्वों पर चर्चा करना।

कार्यशाला के विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञों द्वारा वार्ता एवं परस्पर चर्चा के माध्यम से दोनों महत्वपूर्ण योजनाओं के विषय में उपयोगी तथा सार्थक जानकारियाँ एवं मार्गदर्शन प्रदान किया गया। प्रथम कार्यशाला का उद्घाटन खण्डवा जनपद के जिलाधिकारी श्री निकुंज श्रीवास्तव ने किया तथा द्वितीय कार्यशाला का उद्घाटन नगर पालिका निगम के महापौर मा. श्री वीर सिंह हिन्डौन ने किया। उक्त कार्यशालाओं में श्री सोमनाथ झारिया, नगर आयुक्त, खण्डवा तथा श्री विवेक सिंह, डिप्टी कलेक्टर, खण्डवा भी उपस्थित थे। तीसरी कार्यशाला का उद्घाटन उज्जैन नगर पालिका निगम की महापौर सुश्री सोनी मेहर ने किया। इन कार्यशालाओं में क्रमशः 35, 42 तथा 29 अधिकारियों, पार्षदों तथा प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग लिया।

उपरोक्त तीनों कार्यक्रमों का निर्देशन डा. उर्मिला बग्गा, संयुक्त निदेशक द्वारा किया गया।

A Case Study of Swayamshree Federation of Orissa

Micro finance is a tool for poverty alleviation and empowerment of poor. Self Help Groups based micro finance has been promoted in India too. However, micro financial activities are mainly confined to rural areas. Swayamshree is a model of SHG's Federation formed and strengthened in Cuttack, Orissa for providing alternative banking services to urban poor under the aegis of CUSIP-DFID/CMC being inspired by Mumbai based NGO - SPARC in 1994. The need for networking among SHG's was felt in 1996 and informal federation was formed for strengthening SHGs through mutual learning and assistance. The Federation was established in August 1998 under CUSIP-DFID Project after having exposure of Gramin/ASA/BURO(T) in Bangladesh. CARE CASHE and Shamshree partnership was initiated by virtue of an agreement in January, 2002. CUSIP-DFID and CARE CASHE were phased out after March. 2002 and September 2006, respectively. The Federation is functioning well without support from banks, and Government agencies. The Federation has been registered under Orissa Self Help Cooperative Act 2001, FCRA, Govt. of India and SRA Act 1860. The target groups of Federation are poor and vulnerable women of Cuttack district. The Federation is managed by a Governing Body, comprising of Chairperson, Chief Executive Officer, Project Officer while Coordinator coordinates over all planning and programme implementations. The salient features of the Federation are as follows:

- Ist Federation of Self Help Group in Urban setup
- Controlled, owned and managed by urban poor women clients
- Rotation of leadership through democratic process
- Cliental base enhanced to 8305 despite prosence of various micro finance players,

सूक्ष्म वित्त निर्धनता उन्मूलन तथा निर्धनों के सशक्तीकरण हेत् एक उपकरण है। स्वयं सहायता समूह आधारित सूक्ष्म वित्त भारत में भी प्रोन्नत किया गया है तथापि सूक्ष्म वित्त गतिविधियाँ मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ही केन्द्रित हैं। स्वयंश्री स्वयं सहायता समूहों का एक संघ का माडल है जिसे उडीसा के कटक में गठित व विकसित किया गया। इसका उददेश्य नगरीय निर्धनों को वैकल्पिक बैंक की सेवाएं उपलब्ध कराना है इसे सी.यू.एस.आई.पी., डी.एफ.आई.डी. / सी.एम.सी. के तत्वावधान में गठित किया गया। जबकि इसे बम्बई आधारित स्पार्क संस्था से 1994 में प्रेरणा मिली। 1996 में स्वयं सहायता समुहों के मध्य समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की गयी और परस्पर सीख तथा सहायता द्वारा स्वयं सहायता समृहों को सशक्त करने हेत् एक औपचारिक संघ गठित किया गया। बांग्लादेश के ग्रामीण / आशा / बी.यू.आर.ओ.(टी.) के यात्रा भ्रमण से सीख के उपरांत संघ का गठन सी.यू. एस.आई.पी., डी.एफ.आई.डी. परियोजना के अंतर्गत किया गया। केयर कैश तथा स्वयंश्री के मध्य एक करार 2002 में हुआ तथापि डी.एफ.आई.डी. तथा केयर कैश परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। सरकारी संस्था व बैंक की सहायता के बिना संचालित है। इसे उड़ीसा स्वयं सहायता सहकारिता अधिनियम, 2001, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, भारत सरकार तथा एस०आर०ए० अधिनियम. 1860 के तहत पंजीकृत कराया गया है। संघ के लक्षित समूह निर्धन तथा जोखिम ग्रस्त महिलाएं हैं। संघ एक शासकीय इकाई जिसमें अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, परियोजना अधिकारी शामिल हैं, द्वारा शासित हैं जबकि संयोजक सभी नियोजन तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन को संयोजित करता है। संघ की प्रमुख विशिष्टताएं निम्न हैं :-

- नगरीय भारत में स्वयं सहायता समूहों का पहला संघ
- नगरीय निर्धन महिलाओं द्वारा नियंत्रित,

Government and other financial institutions

- Effective coordination with stakeholders like Cuttack Municipal Corporation and other line Departments in the city.
- Comparatively low cost services in urban areas
- Credit demand is absolutely met out of member's savings without any bank linkage
- Frequent need based credit disbursement
- Launch of livelihood programme in collaboration with Manav Vikas, Bhubaneshwar.
- Initiation of health services to clients in collaboration with NABARD.
- Initiation of insurance services to clients in collaboration with LIC of India and New India Assurance Ltd.

The Federation has out reach of 79 slums of Cuttack city. It has formed 750 SHG'S with membership of more than 10,000. The cliental coverage has been reported to be 8305. The present assets of the federation are valued at Rs. 1.34 crores. The amount of savings mobilized is reported to be Rs. 1.90 crores. Average saving per member has been reported to be Rs. 1840 while monthly saving per SHG's is Rs. 450. The Federation provides 4 per cent interest on savings to clients. It paid Rs. 9.46 lakh as interest on savings to clients in 2006 while 599 beneficiaries of 43 groups were provided incentive of Rs. 33480 under Swarn Jayanti Shahari Rojgar Yojana. The Federation disbursed loan of Rs. 5.10 crores with the average amount of Rs. 30,770 per SHG. The recovery rate has been reported to 97 per cent. The Federation has covered 710 members of SHG's under Surakshya insurance scheme while 3000 members have been covered under Royal Sundaram Insurance Company Pvt. Ltd. Birla Sunlife Insurance has also covered 502 members of SHG's. The Federation has initiated

- व्यवस्थित तथा स्वामित्व में कार्यरत
- लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नेतृत्व का परिवर्तन
- विभिन्न सूक्ष्म वित्त अभिकर्ताओं, शासकीय तथा वित्तीय समस्याओं के बावजूद उसका ग्राहक आधार 8305 तक पहुँचा
- विभिन्न इकाइयों जैसे कटक नगर निगम तथा अन्य विभागों के साथ प्रभावी संयोजन
- नगरीय क्षेत्रों में निम्न लागत सेवाएं
- बिना बैंक संयोजन के ऋण आवश्यकताओं को सदस्यों की बचत से पूरा किया जाता है
- आवश्यकतानुरूप ऋण वितरण की बारम्बारता
- आजीविका कार्यक्रम की शुरूआत मानव विकास, भुवनेश्वर के साथ किया
- स्वास्थ्य सेवाओं की शुक्तआत एन.ए.बी.ए.आर.डी. के सहयोग से किया।
- बीमा सेवाओं की शुरूआत भारतीय जीवन बीमा निगम, रायल सुन्दरम् तथा न्यू इण्डिया इश्योरेंस लि. के सहयोग से की।

संघ की पहुँच कटक नगर निगम के 79 गंदी बस्तियों में है। इसने 750 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया है जिनमें लगभग 10,000 सदस्य हैं। इसका ग्राहक आधार 8305 है जबकि इसकी परिसम्पत्तियों की कीमत लगभग 1.34 करोड़ रूपये है। सहायता समूहों की बचत राशि लगभग 1.90 करोड़ रूपये दर्ज की गयी जबकि प्रति सदस्य बचत 1840 रूपये दर्ज की गयी और प्रतिमाह प्रति समूह औसत बचत ४५० रूपये है। संघ बचत पर ४ प्रतिशत का ब्याज देता है। इसने 2006 में बचत पर ब्याज के रूप में 9.46 लाख रूपये अपने ग्राहकों को दिये जबकि 599 लाभार्थियों को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत प्रोत्साहन दिये गये। संघ ने 5.90 करोड रूपये का ऋण बॉटा जबकि प्रति समूह ऋण 30.770 रूपये दर्ज किया गया। संघ की ऋण वसूली पर 97 प्रतिशत पायी गयी। सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 710 सदस्य तथा रायल सुन्दरम बीमा कम्पनी के द्वारा 3000 सदस्यों, बिड़ला सन लाइफ बीमा द्वारा 502 सदस्यों को बीमा योजना के अंतर्गत आच्छादित किया गया। संघ ने व्यावसायिक training programmes for vocational skills, entrepreneurship development and livelihood development in collaboration of established NGO's and private sector. It has also initiated social intermediation through addressing social problems. Moreover, the Federation has developed training models and policy of micro finance. The success story of Shayamshree may be replicated in other poverty prone cities and towns of the country.

प्रशिक्षण, उद्यमशीलता विकास तथा आजीविका हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन स्वैच्छिक संस्थाओं तथा निजी संस्थाओं के सहयोग से कर रहा है। संघ सामाजिक समस्याओं के हल हेतु सामाजिक मध्यस्थता की पहल भी की है। इसमें प्रशिक्षण मैनुअल तथा सूक्ष्म वित्त पर नीति भी विकसित की है। स्वयंश्री की सफल कहानी को देश के अन्य निर्धनग्रस्त शहरों तथा नगरों में भी लागू किया जा सकता है।

SPECIAL ACTIVITIES

National Seminar on Role of Urban Local Government in Disaster Management

A two-day National Seminar on Role of Urban Local Government in Disaster Management was organized by the Regional Centre for Urban and Environmental Studies, Lucknow on 23rd and 24th March, 2007 at RCUES Conference Hall, Lucknow. The seminar was held under the joint auspices of the Ministry of Urban Development, Government of India, New Delhi, and Department of Urban Development, Government of Uttar Pradesh, Lucknow. The principal objectives of the seminar were:

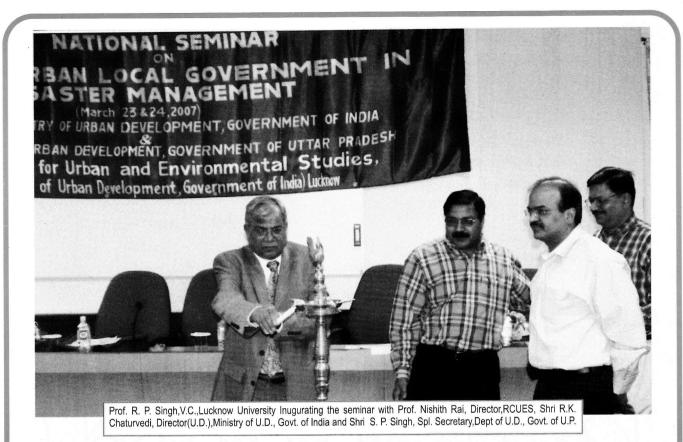
- To review the status, situation, dimensions and trends of disasters and their impact on development;
- To examine role of government agencies in disaster mitigation and response;
- To examine the role of local self governments in disaster mitigation and response;
- To examine the role of NGO's, community based organizations, and other stakeholders in disaster management;
- To review the status of disaster management strategies, and also the functioning of committees, commissions and institutions aiming disaster mitigation and response;
- To discuss the scope and prospects of disaster mitigation planning;
- To discuss institutional arrangements for urban risk mitigation;

आपदा प्रबंधन में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र ने आपदा प्रबंधन में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका पर एक दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन लखनऊ में 23 व 24 मार्च, 2007 को किया। संगोष्ठी के निम्न उददेश्य थे:-

- आपदाओं के विभिन्न आयामों, प्रवृत्तियों, स्थिति तथा विकास पर उनंके प्रभाव की समीक्षा करना;
- आपदा को न्यून करने तथा उससे बचाव हेतु नीतियों पर विचार करना:
- आपदा प्रबंधन में स्थानीय निकायों, स्वैच्छिक संस्थाओं तथा सरकारी संस्थाओं की भूमिका का परीक्षण करना:
- आपदा प्रबंधन के विधिक तथा नीतिगत ढांचे पर विचार करना;
- आपदा प्रबंधन में सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यक्रमों, परियोजनाओं तथा योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना;
- आपदा प्रबंधन के बचाव, प्रतिउत्तर, पुनर्वासन तथा पुनर्संरचना हेतु रणनीतिक नियोजन की रूपरेखा प्रस्तुत करना;
- आपदा प्रबंधन में आ रही विभिन्न अड़चनों, कितनाइयों तथा चुनौतियों का परीक्षण करना तथा उनके समाधान हेत् उपाय सुझाना।

संगोष्ठी का उद्घाटन लखनऊ विश्वविद्यालय के



- · To share experiences in managing disasters;
- To suggest policy measures for disaster mitigation and response.

The seminar was inaugurated by Prof. R.P. Singh, Vice-Chancellor, Lucknow University, Lucknow. He talked about various types of disasters in Indian perspective and highlighted the role of urban local bodies, NGO's and educational institutions in disaster management. Sri R.K. Chaturvedi, Director (UD), Ministry of Urban Development, Government of India, New Delhi in his presidential remarks said that disaster management needs multi-dimensional approaches and involvement of various stakeholders. The seminar was divided into four technical sessions besides sessions of inauguration, plenary, special, and validictory. Overall 46 papers and presentations were presented by deligates and scholars. The seminar was attended by 86 persons while representation of 14 states viz. Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Delhi, Himachal Pradesh, Orissa, Karnataka, Kerala, Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttaranchal, and Uttar Pradesh were ensured in the seminar. The eminent delegates included Prof. Vinayak Choudhary (Guwahati), Sri G. Srinivas Rao (Hyderabad), Sri Yogendra Tripathi (Patna), Sri Rajeev Kumar Shukla (Delhi), Dr. Ram Boojh (Delhi), Dr. P.K. Banta (Shimla), Prof. K.S. Padhy (Berhampur), Sri Ashok Senganel

कुलपति प्रो. आर. पी. सिंह ने किया। उन्होंने आपदा प्रबंधन में अकादिमक तथा शैक्षणिक संस्थाओं के योगदान पर चर्चा करते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों तथा शैक्षणिक संस्थाओं को आपदा प्रबंधन हेतु विभिन्न पाठयक्रमों का संचालन करना चाहिए तथा उत्तम मानव संसाधन तैयार करना चाहिए। संगोष्ठी में एक आधारभूत प्रपत्र प्रो. निशीथ राय तथा डा.ए.के. सिंह ने संयुक्त रूप से तैयार कर प्रस्तुत किया। इस संबंध में आपदा प्रबंधन के विभिन्न आयामों, पहलुओं तथा पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गयी है। संगोष्ठी के विभिन्न तकनीकी सत्रों में आपदा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न पक्षों, पहलुओं, परिप्रेक्ष्य, मुद्दों तथा विषयों पर लगभग 46 प्रपत्रों का प्रस्तुतीकरण किया गया। संगोष्ठी में 86 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इन में 14 राज्यों के शिक्षाविद, नगर निकायों के प्रतिनिधि, अधिकारी तथा स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल थे। विशिष्ट अतिथियों में प्रो. विनायक चौधरी (गोहाटी), प्रो. के. एस. पाढ़ी (बरहमपुर), प्रो. रवीन्द्र शर्मा(जयपुर), प्रो.आर.डी.सिंह (भोपाल), प्रो. आर.पी.सिंह(कानपुर), डा.एस.पी. सिंह (भोपाल), डा. लिपि मुखोपाध्याय (दिल्ली), डा. अजय चौरसिया (रूडकी), सुश्री वन्दना चौहान (अहमदाबाद), डा. अशोक सेगानेल (मैसूर), प्रो. अशोक कुमार (हैदराबाद) आदि शामिल थे।

(Mysore), Sri P.P. Balan (Tiruchur), Prof. Ravindra Sharma (Jaipur), Prof. R.D. Singh (Bhopal), Sri Ajai Chaurasia (Roorkee), Prof. R.P Singh (Kanpur), Dr. Shudhakar Shukla (Lucknow).

The principal recommendations of the seminar were:

- There should be a comprehensive 'Training Manuals' encompassing of situation analysis of disasters, preventive and risk reduction measures, resources and other vital information in order to provide capacity building to the manpower and representatives of local bodies/civil societies and other stakeholder agencies.
- Applications of GIS and remote sensing should be encouraged in order to effectively analyze and interpret the available data for risk reduction.
- Best practices pertaining to disaster mitigation and management should be documented properly and be disseminated in vernacular language and pictorial format to the community.
- Specific coursewares should be designed and be implemented by all educational institutions to inculcate education and knowledge among the school going children, NGOs, and other government agencies.
- In order to create awareness and sensitization regarding risk, hazard, disaster mitigation and management among the community, the activities of different implementing agencies should be strictly monitored and responsibility should be entrusted to the concern agency.
- Coordination, knowledge networking among the various stakeholders, researchers, academicians, and NGOs is imperative and should be updated on regular basis by a nodal agency.
- Effective implementation of building bye-laws be ensured by the state government and the role of local bodies in construction of buildings and infrastructure should be strengthened in order to promote earthquake resistant design and construction of buildings as well as to reduce risk.
- Training of artisans, masons and engineers about earthquake resistant measures should be imparted in order to propagate the principles of earthquake resistant design of buildings, which will immensely reduce the vulnerability of buildings and also the new construction, taking all the earthquake resistant measures into account.
- There should be provision of minimum 1000 temporary intermediate shelters as a infrastructure

संगोष्टी के समापन सत्र की अध्यक्षता श्री अनिल कुमार सागर, निदेशक स्थानीय निकाय, उ. प्र. ने की जबिक विशिष्ट अतिथि श्री बी. पी. सिंह, आई. जी. (अग्नि सेवायें), उ. प्र. शासन थे। श्री बी. पी. सिंह ने कहा कि आपदा प्रबंधन हेतू विकेन्द्रीकृत व्यवस्था का प्राविधान किया गया है तथापि स्थानीय निकायों की भुमिका बहुत सीमित है। शहरों तथा नगरों में डिजिटल मैपिंग की जरूरत है जिससे कि आपदा जोखिम को कम किया जा सके तथा उचित प्रबंधन हेत् उचित व्यवस्था की जा सके। श्री अनिल कुमार सागर ने कहा कि स्थानीय निकायों को अधिकारों का हस्तांतरण पूरा नहीं हो सका है अतः हस्तांतरण की प्रक्रिया को पूरा करना होगा और आपदा प्रबंधन में स्थानीय निकायों को अधिक सशक्त बनाना होगा। संगोष्टी में चर्चा के दौरान निम्न संस्तृतियाँ उभर कर आयीं :-

- भूकम्प के जोखिम को कम करने हेतु यह संस्तुति की गई है कि प्राथमिकता के आधार पर 'सियस्मिक माइक्रोजोनेशन' अध्ययन लिया जाये, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में लोगों का पलायन एवं खराब गुणवत्ता के भवन निर्माण से ज्यादा जीवन एवं वित्तीय हानि पहुँच सकती है। शहरों में कनजोर भवनों को चिन्हित करके उनका जीर्णोद्धार किया जाये।
- सुरक्षित सार्वजनिक भवनों को चिन्हित करना जिससे कि उनको आपदा राहत केन्द्रों में बदला जा सके।
- राहत केन्द्रों तक पहुँचने हेतु सुरक्षित मार्गों का चिन्हांकन करना।
- भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित सूक्ष्म क्षेत्रों के मानचित्रों को दर्शाना।
- स्थानीय स्तर पर अभियंताओं, मिस्त्रियों तथा मजदूरों को भूकम्प अवरोधी भवनों के निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जाय।
- शैक्षिक संस्थाओं, नगर निकायों तथा अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी अधिकारियों, प्रतिनिधियों तथा जनता को जानकारी तथा प्रशिक्षण देने हेतु स्थानीय भाषा में प्रशिक्षण मैनुअल को तैयार किया जाय। इस मैनुअल में आपदाओं से संबंधित विभिन्न आयामों, वस्तुस्थिति विश्लेषण, संसाधनों तथा अन्य प्राविधानों का विवरण दिया जाय।
- आपदा के जोखिम को कम करने हेतु भवन बाई—लॉज का क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाय और भवन निर्माण कार्यों में

facility at District HQ, which can be put to the affected areas within 24 hours for the affected people, and after permanent settlement of affected people the same can be brought to District HQ.

- In order to reduce risk after earthquake strikes, it is strongly recommended that seismic microzonation studies of cities should be taken-up on high priority basis since due to shift of rural population to urban areas vis-a-vis bad quality of construction may lead to more loss of life and economic losses.
- There should be proper institutional arrangements for retrofitting the buildings according to building codes and investment for such assistance scheme.
- Involvement of private sector in disaster mitigation and management is imperative. Similarly, creating conditions for the development of insurance markets, and encouraging the use of other risk reduction financial instruments are need of hour.

- स्थानीय निकायों की भूमिका को सुनिश्चित किया जाय।
- आपदा प्रबंधन में एच.ए.एम.रेडियो संचालकों की अहम भूमिका है। अतः समुदाय रेडियो तथा ऐसे संचालकों को आपदा प्रबंधन हेतु प्रोत्साहन दिया जाय।
- आपदा जोखिम बचाव तथा प्रबंधन हेतु विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रमों को विकसित किया जाय जिससे कि स्कूल तथा कालेज जाने वाले बच्चों तथा अन्य व्यक्तियों की जानकारी का स्तर बढाया जा सके।
- आपदा जोखिम के चित्रांकन तथा विश्लेषण में भौगोलिक सूचना प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः शहरों तथा नगरों में डिजिटल मैपिंग को सुनिश्चित किया जाय।

संगोष्ठी का संचालन डा.यू.बी.सिंह, संयुक्त निदेशक तथा डा. अवधेश कुमार सिंह, सहायक निदेशक ने संयुक्त रूप से किया।

Workshop on Public Private Partnership in Urban Services Manual

The Regional Centre for Urban & Environmental Studies, Lucknow organized a one day Workshop on "Presentation of Public Private Partnership Manual" on 21st march 2007 at the Centre's conference hall. Under the Capacity Development Project being implemented by the Centre in all the 51 Class-I towns of U.P. The Centre has prepared a draft manual which would help in implementation of Public Private partnership in Urban services. The objective of the Workshop was to discuss the Draft Manual prepared and suggest additions and changes if required in the manual so that final shape can be given to it.

The workshop was inaugurated by Shri Anil Kumar Sagar, Director, Directorate of local Bodies, Govt. of U.P. In his inaugural address Shri Sagar expressed that the role & responsibilities of ULBs has increased tremendously but the ULBs lack the latest know-how for improved service delivery to enhance the service quality & efficiency. Public Private Partnership is essential. He was of the view

नगरीय सेवाओं हेतु सार्वजनिक—निजी भागीदारी मैनुअल पर कार्यशाला

क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ ने अपने सभागार में 21मार्च, 2007 को एक दिवसीय कार्यशाला "सार्वजनिक—निजी क्षेत्र की भागीदारी पर आधारित मैनुअल के प्रस्तुतीकरण" का आयोजन किया। नगरीय शासन हेतु क्षमता विकास परियोजना, के अंतर्गत जिसे केन्द्र प्रदेश के 51 प्रथम श्रेणी शहरों में क्रियान्वित कर रहा है, हेतु एक ड्राफ्ट मैनुअल तैयार कराया गया है जो नगरीय सार्वजनिक सेवाओं में निजी भागीदारी को क्रियान्वित करने में मदद देगा। इस कार्यशाला का उद्देश्य ड्राफ्ट मैनुअल पर चर्चा करना था ताकि उसमें वांछित बदलाव लाया जा सके और उसे अंतिम रूप दिया जा सके।

कार्यशाला का उद्घाटन श्री अनिल कुमार सागर, निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ. प्र. शासन ने किया। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि स्थानीय निकायों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गये हैं जबिक उन्हें सेवा प्रदायता हेतु अद्यतन जानकारी का अभाव है। सेवा, गुणवत्ता तथा प्रभावकारिता में सुधार हेतु सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी आवश्यक है। उनका मत है कि that PPP can be involved in many ways but a uniform structure is required, with this objective a manual is being developed which will go a long way in improving the service delivery of the ULBs.

The panel discussion was chaired by Shri S.P. Singh, Special Secretary, Dept. of Urban Development, Govt. of U.P. He expressed that the Public Private Partnership Manual should be comprehensive and should serve as an ultimate handbook for the ULBs in order to help them involve private participation for providing improved efficient Urban services. In all 33 participants consisting of Mayors of Jhansi Nagar Nigam & Allahabad Nagar Nigam, Chairmans of Nagar Palika Parishad Basti &Kannauj, Municipal Commissioners, Executive Officers of Class-I Towns, Officers of the Directorate of Local Bodies, U.P. attended the workshop. During the workshop several valuable suggestions and recommendations came up which are now being incorporated in the Manual.

The workshop was coordinated by Dr. Rajeev Narayan, Dy. Director, RCUES.

सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी अनेक तरीकों से विकसित की जा सकती है तथापि एक सार्वभौमिक ढांचे की जरूरत है। इसी उद्देश्य हेतु मैनुअल तैयार किया गया है जो स्थानीय निकायों में सेवा प्रदायता को सुधारने में मदद करेगा।

पैनल परिचर्चा की अध्यक्षता श्री एस. पी. सिंह, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ. प्र. शासन ने की। उन्होंने कहा कि नगरीय सेवाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाने हेतु स्थानीय निकायों हेतु एक विस्तृत तथा व्यापक सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी मैनुअल की जरूरत है जो एक हैण्डबुक का उद्देश्य पूरा कर सके। कार्यशाला में 33 प्रतिभागियों ने भाग लिया जिसमें झांसी, इलाहाबाद नगर निगम के महापौर तथा बस्ती, कन्नौज नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, नगर आयुक्त, प्रथम श्रेणी के नगरों के अधिशासी अधिकारी तथा उ. प्र. स्थानीय निकायों के अधिकारी शामिल थे। कार्यशाला के दौरान मैनुअल हेतु अनेक महत्वपूर्ण सुझाव एवं संस्तुतियां आयीं जिन्हें मैनुअल में शामिल किया जा रहा है।

कार्यशाला का संचालन डा. राजीव नारायण, उप निदेशक ने किया।

© GOI-UNDP's Project on Capacity Development for Decentralized Urban Governance

Under this project four towns of U.P. viz. Allhabad, Varanasi, Meerut & Mathura have been selected. The RCUES as State Level Impementing Agency is implementing Accounting Reforms through Double Entry System of Accounting and Property Tax Reforms through implementation of Geographical Information System (GIS).

Work done under the Project:

- Double Entry System of Accounting-Field Level Consultants appointed.
- Geographical Information System(GIS)agencies identified and work started.

The work is being coordinated by Dr. Rajeev Narayan, Dy. Director, and assisted by Dr. Alka Singh, Research Associate.

विकेन्द्रीकृत शासन हेतु क्षमता विकास पर भारत सरकार—संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना कार्यक्म

परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के चार शहरों— इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ तथा मथुरा का चयन किया गया है। राज्य स्तरीय कियान्वयन एजेंसी के रूप में क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र दोहरी लेखा प्राणाली द्वारा लेखा सुधार एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली द्वारा सम्पत्ति कर सुधार लागू कर रहा है।

परियोजना के अंतर्गत निम्न कार्य किए गये हैं :--

- लेखा की दोहरी प्रणाली स्थानीय स्तर पर परामर्शदाताओं की नियुक्ति
- भौगोलिक सूचना प्रणाली— एजेंसियों की पहचान तथा कार्य की शुरूआत

परियोजना का संचालन डा. राजीव नारायण, उप निदेशक कर रहे हैं जबकि डा. अलका सिंह, शोध सहयोगी उन्हें सहयोग कर रही हैं।

Oouble Entry Accounting System

The Regional Centre is Coordinating the Implementation of Double Entry Accounting System in ULB's of U.P. Draft DEAS Manual has been approved by the Expert Management Group(EMG), and submitted to the Government of U.P. for adoption.

The work is being coordinated by Dr. Rajeev Narayan, Dy. Director, and assisted by Dr. Alka Singh, Research Associate.

Solid Waste Management

The Regional Centre in its capacity as Nodal Agency has prepared Detailed Project Reports for 6 JNNURM Towns and 21 UIDSSMT Towns. Out of which 19 DPRs have been sanctioned by the Govt. of India.

The work of implementation of Integrated Solid Waste Management in 19 towns of U.P. is in progress.

The work is being coordinated by Dr. Rajeev Narayan, Dy. Director, and assisted by Dr. Alka Singh, Research Associate.

Slaughter House Waste Management

The Regional Centre has prepared 5 DPRs for Modernization of Slaughter Houses at Rampur, Aligarh, Khurza, Meerut and Unnao. Expression of Interest has been called for setting up a Modern Slaughter House at Khurza on PPP basis. The work will start shortly.

The work is being coordinated by Dr. Rajeev Narayan, Dy. Director, and assisted by Dr. Alka Singh, Research Associate.

लेखा की दोहरी लेखा प्रणाली

क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, दोहरी लेखा प्रणाली का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश के नगर निकायों में कर रहा है। दोहरी लेखा प्रणाली का ड्राफ्ट मैनुअल एक्सपर्ट मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है और उसे प्रदेश सरकार के पास लागू करने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

इस कार्य का समन्वयन डा. राजीव नारायण, उप निदेशक कर रहे हैं । उन्हें डा. अलका सिंह, शोध सहयोगी उन्हें सहयोग दे रही हैं।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन

क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु एक नोडल एजेंसी के रूप में जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत 6बड़े तथा 21 छोटे एवं मझले शहरों में शहरी बाह्य संरचना विकास योजना के अंतर्गत चयनित शहरों में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया है। इनमें से 19 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुके हैं। एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य प्रदेश के 19 शहरों में प्रगति पर है।

इस कार्य का समन्वयन डा. राजीव नारायण, उप निदेशक कर रहे हैं जबकि डा. अलका सिंह, शोध सहयोगी उन्हें सहयोग कर रही हैं।

पशुवधशाला अपशिष्ट प्रबंधन

क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र ने रामपुर, अलीगढ़, खुर्जा, मेरठ तथा उन्नाव में पशुवधशालाओं में आधुनिकीकरण हेतु 5 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये हैं। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी के आधार पर खुर्जा में आधुनिक पशुवधशाला की स्थापना हेतु 'एक्सप्रेशन आफ इंट्रेस्ट' आमंत्रित किए गये हैं। जल्द ही कार्य शुरू होने की संभावना है।

कार्य का समन्वयन डा. राजीव नारायण, उप निदेशक कर रहे हैं जबकि डा. अलका सिंह, शोध सहयोगी उन्हें सहयोग कर रही हैं।

FACULTY NEWS

Dr. Urmila Bagga

 Attended and participated in a training programme on "Strengthening Urban Management in India" organized by Administrative Staff College of India, in collaboration with World Bank Institute, Washington at Hyderabad from January 22-26, 2007.

Dr. Richa Varmani

· Participated in meetings of Committe to Amend Bye Laws of Lucknow Cantonment Board.

Dr. Rajeev Narayan

• Attended 5 days training programme on "Strengthening Urban Management in India" organized by Administrative Staff College of India, in collaboration with World Bank Institute, Washington at Hyderabad from January 22-26, 2007.

Dr. A.K. Singh

- Attended workshop for Formation of City Managers Association U.P. organized by USAID-FIRE (D) Project at Clark's Awadh Hotel, Lucknow on February 2, 2007.
- Participated in National Seminar on Problems Faced by Women Representatives in PRI's in India, sponsored by National Commission for Women, New Delhi, organized by G.B. Pant Institute of Studies in Rural Development, Lucknow on 10th February 2007.
- Participated in State level workshop on "Towards A Safe Bihar Dissater Risk Management Programme" organised by UNDP-DRM Project, Government of Bihar at Patna, on 23 Februrary 2007.
- Attended International Conference on "Tribal Development and Social Change" organized by D.N. Majumdar Ethnographic Folk Culture Society, Lucknow on 22-24 February 2007.
- Participated in Workshop on "Disaster Management in U.P." organized by Nehru Yuva Kendra Sanghatan, Lucknow at Literacy House, Lucknow on 23rd February 2007.
- Participated in workshop on "Designing Intervention for Prevention of HIV/AIDS for Police Personnel in U.P." supported by UNAIDS and organised by Sristhi, Gomti Nagar, Lucknow on 24th February, 2007.

FORTHCOMING PROGRAMMES

- Orientation Training Programme on Swarn Jayanti Sahari Rojgar Yojana for Executive Officers of Urban Local Bodies in Orissa on 23rd and 24th April 2007 at Bhubaneshwar.
- Refresher Training Programme on Swarn Jayanti Sahari Rojgar Yojana for Executive Officers of Urban Local Bodies in Orissa on 25th and 26th April 2007 at Bhubaneshwar.
- Workshop on Swarn Jayanti Sahari Rojgar Yojana for Executve Officers and Community Organisers of Urban Local Bodies in Orissa on 27th April 2007, at Bhubaneshwar.
- Workshop on Swarn Jayanti Sahari Rojgar Yojana for Community Organizers of Urban Local Bodies in Orissa, on 28th April 2007, at Bhubaneshwar.
- Training programme on Community Participation in Urban Development on June 4-6, 2007 at Patna.
- Training Programme on IT and E-Governance in Municipal Administration on June 4-8, 2007 at Lucknow.
- Training Programme on Managing Urban Transport on June 25-27, 2007 at Lucknow.

ACADEMIC CALENDER

S.No.	Name of Programmes	Objectives & Focus Areas	Level of Participants	Venue	Duration 8	
1.	Community Participation in Urban Development	The basic objective of the programme is to build capacity resources in order to achieve community participation and project development. Contents Concept of community participation – its purpose and uses. Information and communication technologies to facilitate community participation including new methodologies and strategic approaches to community development. Opportunities for the development of revenue generation for community projects.	Executive Officers and elected representativ es of ULBs	Patna	Dates Three days June 4-6, 2007	Dr. Padma lyer impadma@hotmail.com
	10	 Networking cooperation and transition exchange. Reinforcing community structures to offset loss of social cohesion and adverse impact of urbanization RTI and Citizens Charter.)	C	
/ i	IT & E- Governance in Municipal Administration	Objectives: The objectives of the training would be: to acquaint the participants with the need & importance of IT & E-Governance in municipal	Senior and middle level officials of urban local bodies and	Lucknow	Five days June 4-8, 2007	
		administration, to acquaint the participants with the technologies & their applications in E-Governance. to orient the participants with the various techniques of E-Governance Contents: Introduction to basics of Information Technology & its use in e-Governance Techniques of e-Governance	parastatal agencies.			Dr. U. Bagga urmila_bagga@yahoo.co.in
		 IT &e-Goveranace and their use & importance in: Planning, Management, Forecasting and Analysis Role of E-Governance for achieving Good Governance. 				
	GIS for Property Tax	 Key objectives: To highlight the need and importance of GIS for Property Tax. Integration of e-Governance with GIS 	Addl./Asstt./ Deputy Municipal Commissioner from Nagar	Lucknow	Three days June 18- 20, 2007	

S.No.	Name of Programmes	Objectives & Focus Areas	Level of Participants	Venue	Duration & Dates	Director
		Focus Areas: GIS as a tool of e-Governances GIS for Property Tax Actions to be taken for implementing GIS Use of GIS and its importance	Nigams, Executive Officers/ Engineers from ULBs			Dr. U.B. Singh ubsingh_56@yahoo.com
4.	Managing Urban Transport	Principles of urban transport planning that promotes green environment, equity amongst citizens. Concept of greening of urban transport Mass rapid transit systems. Focus Areas: Planning and developing sustainable transport systems Urban transport and environment Scope of railway transport in	Transport Officials, Engineers from ULBs and Development Authorities.	Lucknow	Three days June 25- 27, 2007	Dr. A.K. Singh awadhesh.rcues@gmail.com
7		urban areas – both metro and mono rail	7 /		- 7	
5.	Reforms in Urban Governance	Objectives ❖ To examine the emerging role of urban administrators in the changing urban scenario. ❖ To familiarize the participants with the status of reforms under JNNURM & associated schemes.	Technical Officers from the urban local bodies, Development Authorities, Housing	Lucknow	Five days July 2-6, 2007	<i>y</i>
		 To emphasize on the need for transparency in urban governance. To familiarize the participants with the various tools and techniques to promote transparency and accountability in urban, administration. Focus Areas Emerging role of Urban Management Urban Reforms agenda and its implementation Need for Transparency in Urban 		Authorities, Housing Board, Jal Nigam,Town and Country Planning Department		Dr. A.K. Singh awadhesh.rcues@gmail.com
2		 Management Citizens Charter Right to Information Act and e-governance Role of Civil Society in urban governance 				

S.No.	Name of Programmes	Objectives & Focus Areas	Level of Participants	Venue	Duration & Dates	Course Director
6.	Management of Urban Services	 Focus Areas: Salient features of 74th CAA Financial resources of ULBs and the need for their mobilization, Resource management Management of urban services Pricing of services, user charges & cost recovery PPP and community participation E-governance at city level 	Senior and middle level administrative & technical personnel from ULBs and other parastatal agencies	Bhopal	Three days July 4-6, 2007	Dr. Anjuli Mishra anjuli_Iko@yahoo.co.in
7.	Management of Solid Wastes	Objectives ❖ To focus on various management issues involved in operating this service ❖ To highlight various low cost technical options available for its management	Executive Officers and Health Officers from the Urban Local Bodies	Varanasi	Three days July 10- 12, 2007	
		To underline the importance of private sector and community participation in effective provision of this service				
	M	To stress the need for inter-agency coordination in the management of the service.	1/1		(\	
		Focus Areas		Mes produced to the control to the control	700	
		 Urbanization vis-à-vis solid wastes management. 		1		E
	and the second	Municipal Solid Waste Manual : Salient Features				Dr. Rajeev Narayan eev_1963@yahoo.com
		MSW Rules and BMW Rules				V Ns
		 Storage, collection and Transportation of solid wastes 				Dr. Rajeev Narayan eev_1963@yahoo.co
	a a	 Disposal of wastes : problems and prospects Recycling of waste 				D
	**	Sewerage treatment & disposal : latest techniques				
		 Guide lines of accessing funds for SWM from XIIth Finance Commission 				
	. T	 Operation & maintenance of SWM System 				
		 Hospital Waste Management 				
	S .	 Plastic waste 			a = 2	
		 Community, civil society and private sector participation in SWM and inter-agency co-ordination Carbon trading Successful case studies 				

S.No.	Name of Programmes	Objectives & Focus Areas	Level of Participants	Venue	Duration & Dates	Course Director
8.	Managing Urban Projects	Objectives To examine the issue of "social planning "versus "physical planning" in urban planning systems To focus on the various institutions and instruments available for guided development To familiarize the participants with the preparation of CDP / DPRs To familiarize the participants with the various aspects of urban planning and stages of project management and To underline the importance of integrated approach to urban planning and project development Focus Areas Urban challenges Concepts of Urban Planning and Project Management Planning norms and standards for key urban services like water supply, solid wastes management, roads, parks & recreational activities etc. Urban Project Management Cycle JNNURM and related projects. Emerging urban management issues like Citizen's Charter, Right to Information, transparency etc. CDP / DPR formulation Heritage guidelines	Executive / Asst. Engineers and Executive Officers from ULBs, Development Authorities, Housing Board, Town and Country Planning Department etc.	Lucknow	Five days July 16- 20, 2007	Dr. U.B. Singh ubsingh_56@yahoo.com
9.	Accrual Based Accounting in Municipal Organizations	 Key objectives: To highlight the salient features of Double Entry Accounting Manual. To underline the need for reforms in this sector and to identify the available courses of actions to bring about the desired changes, To make the municipal financial processes transparent and accountable to all stake holders, and To identify measures to promote transparency and accountability in financial management. Focus Areas: Reforms in budgetary practices including the participatory budgeting, 	Senior and middle level Accounts Personnel from ULBs and other parastatal agencies.	Lucknow	Five days August 6- 10, 2007	Dr. Rajeev Narayan rajeev_1963@yahoo.com

S.No.	Name of Programmes	Objectives & Focus Areas	Level of Participants	Venue	Duration & Dates	Course Director
-	×	 Double entry system and the actions to taken to implement the same and Measures to Improve practices in auditing, including social audit 				
10.	Management of UPA Programmes	Objectives ❖ To examine the status of UPA programmes ❖ To examine the present institutional arrangements for UPA programmes and iJentify their inadequacies ❖ To highlight approaches to participatory planning for UPA programmes and their implementation ❖ To make them aware of the recent Government initiatives in UPA	Executive officers from ULBs and Project / Asst. Project officers from SUDA / DUDA	Bhubane -shwar	Five days Aug.6- 10, 2007	Dr. Padma lyer impadma@hotmail.com
		sector Focus areas Urban Poverty Alleviation Programmes: an overview Institutional arrangements for UPA programmes Participatory planning and implementation Participatory monitoring and appraisal of the projects UPA Programmes: Best Practices				7
11.	Departmental Enquiry and other service matters	Key objectives: To sensitize the officials with the criteria & procedure relating to departmental enquires and to highlight the role of administration To familiarize them with the rules relating to punishments, their imposition, conduct of enquiry and enquiry report etc., To discuss about the legal aspects of departmental enquires as well as other service matters Focus areas: a) Departmental enquires and principles of natural justice b) Code of conduct c) Punishments & their impact d) Procedure for imposition of punishments e) Role and responsibilities of	Senior adminstrative and technical personnel from ULBs and other parastatals	Ujjain	Five days Aug.6- 10, 2007	Dr. U. Bagga urmila_bagga@yahoo.co.in

S.No.	Name of Programmes	Objectives & Focus Areas	Level of Participants	Venue	Duration & Dates	Course Director
	A V	f) Suspension g) Enquiry report, appeal and reviews				
		h) Confidential report and adverse entry				
12.	Financial Management in Urban Local Bodies	Key objectives: To examine the prevalent intergovernmental financial relations and to identify the areas for reform To highlight the desired arrangements to ensure financial accountability To examine the reforms needed in municipal accounting and auditing systems Focus Areas: Intergovernmental financial	Executive Officers, Accounts Officers/ Accountants fromthe urban local bodies and other parastatal agencies.	Lucknow	Five days Aug.20- 24, 2007	Dr. Richa Varmani richa varmani@yahoo.co.in
		relations Municipal finance: present status and need for reform Municipal budgeting Municipal financial responsibility Reforms in municipal accounting & auditing systems				richa_
13.	Mobilizing Municipal Financial Resources	Key objectives: To emphasize on various methods for optimum utilization of existing financial resources. To familiarize the participants with the innovative financing tools like access to capital markets, Tax free Municipal bonds issue, Pooled financing, Borrowing from Commercial Banks etc.	Executive Officers/ Accounts Personnel from the urban local bodies and officials from parastatal agencies	Lucknow	Five days Sept.11- 15, 2007	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\
		 To highlight the pre conditions for innovative infrastructure financing including the pricing of urban services, and To highlight the need for committed political and administrative leadership. Focus Areas: Review of current financial resources Valuation & Assessment of Municipal Revenue Reforms in Property Tax 				Dr. Anjuli Mishra anjuli_lko@yahoo.co.in
		Administration d. Role of CFC & SFC e. Role & responsibilities of DDO's f. Public-Private Partnership g. Community participation h. Access to Institutional Finance				

3.No.	Name of Programmes	Objectives & Focus Areas	Level of Participants	Venue	Duration & Dates	Course Director
14.	Urban Planning	To orient the officials about the need and importance of urban planning To acquaint them with various components and stages of urban planning To make the urban officials aware of the techniques of urbanplanning To discuss the role of Master Plan in urban planning To highlight the importance of associating community in urban planning for achieving sustainable development	Administrative /Executive Officers, Engineers, Planners and Presidents	Patna	Five days Sept.18- 22, 2007	Dr. A.K. Singh awadhesh.rcues@gmail.com
		Contents: Urban Planning – Charging concept Need and importance of Urban Planning Urban Planning in legal framework Tools & techniques of urban planning Associating stakeholders				
15.	Orientation Programme for Newly Appointed Executive Officers	 Key objectives: To make the officials aware of their duties and responsibilities, To familiarize them with the various legislations relating to urban management, To acquaint them with the working of ULBs including the financial management. 	Newly Appointed Executive Officers	Lucknow	Ten days Sept.19- 28, 2007	ni o.co.in
		Focus Areas: a. Salient features of 74 th CAA b. Financial resources of ULBs and the need for their mobilization c. Tax management d. Municipal budgeting, accounting and auditing e. Management of urban services f. Office management g. UPA programmes h. PPP and community participation i. Disciplinary enquiry and service rules				Dr. Richa Varmani richa_varmani@yahoo.co.in
16.	Orientation Workshop On Right To Information Act	Need to orient emerging trends and patterns of urbanization and their implications on urban governance To discuss the tools and techniques of good urban governance	Executive Officers, elected representativ es of urban local bodies, and parastatal agencies	Lucknow	Three days Oct. 4-6, 2007	

S.No.	Name of Programmes	Objectives & Focus Areas	Level of Participants	Venue	Duration & Dates	Course Director
		To orient the provisions of RTI Act and also powers, functions and obligations of Central and State Information Commissions To examine the problems and challenges in implementation of RTI Act in urban governance Contents Governance Framework for Delivery of Services RTI Act: Salient Features				Dr. U. Bagga urmila_bagga@yahoo.co.in
		 Good Urban Governance Urban Infrastructure Projects Legal Provisions of RTI Act Central and Information Commissions: Powers and Functions of Information Commissions 				D urmila
F 2-10-20		Public Disclosure Act				
	Good Urban Governance: Principles and Best Practices	Key objectives: To make the participants aware of good governance attributes To highlight the need for SMART governance in the changing urban context To highlight the best urban governance practices in the country and else where, and To examine the feasibility of their replication and the consequential change that needs to be undertakenlegislative, administrative etc. Areas: a. Good Goverance: Concept & Attributes b. Municipal structures and organizations c. Financial Management d. Urban Serviçes & e-governance e. Private sector and community participation in urban management f. Successful Case-Studies g. Inter- agency coordination h. Report Card System	Chairpersons, senior administrative personnel Executive Officers, Class I ULBs and parastatal agencies.	Indore	Three days Oct.8-10, 2007	Dr. Anjuli Mishra anjuli_lko@yahoo.co.in
18.	Managing Urban Environment	To discuss emerging issues in urban governance To review the present status of urban environment To discuss the status of urban sanitation - drainage, water supply, sewerage and solid waste management	Executive Officers and Engineers, of Urban Local Bodies, and parastatal agencies	Bhubane- shwar	Three days Oct.29 to Nov.2,20 07	

S.No.	Name of Programmes	Objectives & Focus Areas	Level of Participants	Venue	Duration & Dates	Course Director
		 To discuss issues of pollution - water, air, noise and degradation of water resources To discuss the techniques and strategies for measuring quality of urban environment and its management To discuss problems and constraints in implementation of MSW Rules To discuss the scope of environmental friendly renewal energy resources 				Dr. A.K. Singh awadhesh.rcues@gmail.com
	70	Urbanization and its implications on urban environment Status of urban environment Solid Waste Management Renewal energy resources Central and State Pollution Control Boards Different types of Pollution and their effects Case Studies				Dr awadhesh
19.	Management of Cost Effective Housing schemes	 Key objectives: To highlight the importance of low cost housing in the present urban scenario; To identify available low cost housing policy options To emphasize upon the advance planning, adoption of appropriate management techniques, low cost design and construction material etc. To underline the importance of participatory approach to low cost housing projects.etc., 	Executive / Asst.Engineers from the Municipal Corporations / Class1 cities /Development Authorities and Housing Boards.	Lucknow	Three days Nov.20-23, 2007	hra no.co.in
		a) Housing policy b) Need and importance of low cost housing projects c) Low cost designs, building material and construction techniques d) Financing of low cost housing projects e) Public-private partnerships and communty participation. f) Energy efficient techniques viz. Solar Passive Architecture techniques in the construction of buildings and solar photovoltaic & solar thermal devices / systems for buildings		$u \in u \cap Y$		Dr. Anjuli Mishra anjuli _lko@yahoo.co.in

S.No.	Name of Programmes	Objectives & Focus Areas	Level of Participants	Venue	Duration & Dates	Course Directo
20.	Financing Urban Infrastructure	 ❖ To sensitize the participants with the pivotal role of adequate, efficient and quality infrastructure in the development of urban economy ❖ To familiarize them with the various infrastructure schemes launched by the Central Govt. ❖ To acquaint them with the formulation of CDP / DPR and related guidelines and ❖ To underline the importance of egovernance in managing urban 	Senior Administrative and Technical Officers from the Urban Local Bodies, Development Authorities, Housing Board, Jal Nigam, Town and Country Planning Department etc.	Raipur	Five days Nov.26-30, 2007	h 100.com
		Focus Areas Financial resources of ULBs and need for their mobilization JNNURM and associated schemes Sewerage and Solid Waste Management Formulation of CDP / DPR Planning and management of Water Supply Services Pricing of services, user charges and cost recovery Operation and maintenance of services Urban transport including parking lots Development of Heritage areas and related guidelines Water conservation and rain water	1			Dr. U.B. Singh ubsingh_56@yahoo.com
21.	Reforms in Property Tax System in India	harvesting PPP and community participation Operation and maintenance of services E-governance at city level. Key objectives: To make the participants aware of the principles of the area based property tax system, to acquaint them with necessary tools and techniques for the administration of the new system to highlight the managerial and personnel issues that needs attention while switching over to the new system Measures that need to be taken to ensure that the new system is citizen-friendly and transparent.	Executive officers, Tax Inspectors and elected representatives	Lucknow	Five days Nov.26-30, 2007	Dr. Richa Varmani richa_varmani@yahoo.co.in

S.No.	Name of Programmes	Objectives & Focus Areas	Level of Participants	Venue	Duration & Dates	Course Director
		a. Importance of Property Tax Administration in present urban context. b. Salient features of Area—Based Property tax system c. Implementing the Self-assessment system. d. Changes required for administering the area-based property tax system including computerization of the tax management e. Necessary measures to make the system citizen friendly				
22.	Environmental Impact Assessment (EIA) for Urban Development Projects	Objectives: Concept of and genesis, tools and methods of EIA Statutory provision under the environmental protection and related acts. Importance of EIA in the context of Sustainable Development Acquaintance with the mitigation measures and the principles of EIA Management Case Studies	Technical Personnel of ULBs, Development Authorities and parastatal agencies	Lucknow	Three days Dec.5-7, 2007	Dr. U. Bagga urmila_bagga@yahoo.co.in
23.	Rain Water Harvesting	Objectives: To spread awareness about the immense relevance of rainwater harvesting. To highlight the Role that People and Communities can play in solving the alarming water situation that we face today Focus Areas: Rainwater harvesting(RWH) Urban water scenario Potential of RWH in major cities RWH Planning RWH structure & design Components of RWH Maintenance and Monitoring Preparing cost estimates Impact assessment Policies on RWH	Executive Officers, Town Planners, Engineers from ULBs and Parastatals	Lucknow	Dec.10- 12, 2007	Dr. Richa Varmani richa_varmani@yahoo.co.in

S.No.	Name of Programmes	Objectives & Focus Areas	Level of Participants	Venue	Duration & Dates	Course Director
24.	Management of Urban Water Supply and Sewerage Undertakings	Objectives ❖ To review the existing management practices in relation to O & M of the systems, its management structures, personnel, budgeting etc. & identify the deficiencies. ❖ To underline the adoption of innovative financial mechanism for efficient management of water supply and sewerage undertakings including rationalization of user charges and appropriate pricing policy ❖ To stress upon the need for private sector & community participation in the management of water supply services. Focus Areas ❖ Planning for urban water supply sector Projects ❖ Operation and Maintenance of urban water supply sector Projects ❖ Operation and Maintenance of urban water supply schemes ❖ Key issues in the delivery of water supply services ❖ Pricing policy, user charges & cost recovery ❖ Private sector participation and the need for regulatory mechanism ❖ Community participation ❖ 24x7 Water Supply ❖ Best Practices and Case Study	Senior and middle level technical and administrative personnel from the Jal Nigam, Jal Sansthans, water supply undertakings of the class-I cities	Ranchi	Five days Dec.10- 14, 2007	Dr. A.K. Singh awadhesh.rcues@gmail.com
25.	P.P.P.in Municipal Services	Analysis Objectives to conceptualize and analyze the emerging trends in public-private-partnership to examine different models of public-private partnership to examine the constraints and risks involve in PPP to discuss emerging perspective of urban infrastructure projects. Focus Areas Concept, models and features of PPP Role of regulatory authority and state government in regulating and	Adminstrative and technical personnel from ULBs an and other parastatals	Ranchi	Three Days Dec.15- 17, 2007	Dr. Padma Iyer impadma@hotmail.com

S.No.	Name of Programmes	Objectives & Focus Areas	Level of Participants	Venue	Duration & Dates	Course Director
		 Role of infrastructure financing agencies Experience sharing Management perspective of PPP 				
26.	Master Plan and Zoning Regulations	Key Objectives:	Town Planners, Technical and Administrative Personnel from ULBs, Development Authority and Housing Boards	Gangatok	Five days January 21-25, 2007	Dr. U.B. Singh ubsingh_56@yahoo.com
27.	Municipal Office Management	Key objectives: To discuss the need and importance of office management, To emphasize upon the automation of office procedures. To highlight the importance of computerization of organizational operations. Focus Areas: a) Organization and methods techniques b) Office records maintenance c) Inventory management d) Application of computers in municipal organizations e) Office lay out and space management. f) E-governance	Senior administrative personnels the ULBs and parastatal agencies	Lucknow	Three days Feb.6-8, 2007	Dr. Anjuli Mishra anjuli_Iko@yahoo.co.in

A. 1 SPECIALIZED COMPUTER ORIENTATION PROGRAMMES

Six specialized Computer Orientation Programmes of six days duration will be organized for the Executive Officers, Accounts Personnel and Technical Personnel from ULBs and other Parastatal Agencies.

- Focus and Training DesignCreate document using MS Word
- Use MS Excel for calculation
- Draw graph using MS Excel

- Generate data base using MS. Access
- Draw basic shapes using Autocad
- Internet and E-mail

ORIENTATION TRAINING PROGRAMMES FOR WOMEN COUNCILORS OF U.P.

- Municipal Legislation
- Municipal Organization
- Municipal Services
- Centrally Sponsored Scheme dealing with urban development and UPA programmes
- · Municipal Financial Resources Management
- · Private Sector Participation in Urban Services
- · Civil Society and Municipal Governance
- Inter-Governmental Relations

Duration: Three days

CAPACITY DEVELOPMENT PROGRAMMES UNDER UIDSSMT & IHSDP

Objectives

- To highlight the backdrop of UIDSSMT and IHSDP schemes, their components and implementation process etc.
- To equip the participants with necessary tools and techniques of project planning, preparation, implementation; monitoring and review;
- To underline the importance of convergence of activities.
- To highlight the issues relating to costing, tendering, contracting etc.
- To provide tools for improved financial management systems including budgetary and accounting practices, tax management with reference to property tax and fixation of user charges and related activities.
- To enable them to realize the importance of private sector in urban management
- To underline the importance for community participation and cooperation of elected representatives at all stages of planning and implementation of the projects to promote a sense of ownership and to ensure their sustainability.

It is proposed to cover the following personnel under the capacity development programme:

- Senior officials at the Divisional and District Level
- Senior Personnel at the city level
- Middle level personnel at the city level
- Personnel dealing with budgeting, accounting and auditing
- Elected Representative of civil society, local bodies and CBOs

WORKSHOPS:

1. Urban Planning in New Perspective	Allahabad	December 18-19, 2007
2. Rain Water Harvesting	Lucknow	January 11-12, 2008
3. National Street Vendor Policy	Dehradun	January 17-18, 2008
4. District and & Metropolitan Planning Committees	Lucknow	January 21-2, 2008
5. Municipal Governance Appraisal: Report Card System	Ranchi	February 6-7,2008
6. Role and Responsibilities of Ward Committee	Lucknow	February 12-13, 2008

National Seminar on E-Governance : Challenges and Prospects Lucknow Nov.16-17, 2007



NOW, MARCH 23

o examine the role of local in disaster mitigation and onal Centre for Urban & idies (RCUES) is organisnal seminar on the subject government in disaster Friday. Around 50 offi-the field of administrament, fire services and ed on the first day of the ngh, Vice-Chancellor, augurated the semient in the country like

e in disaster prone on land, high prices nigration and nong constructions,

जनवरी।

आर,के, मित्तल ने केन्द्रीकरण के बिना हीं है। विकेन्द्रीकरण गुणवत्ता और लोगों को सुनिश्चित किया वह विश्वविद्यालय के में क्षेत्रीय नगर एवं यन केन्द्र के तत्वावधान ध्यक्षों की दो-दिवसीय शाला को सम्बोधित कर

can play a crucial role in it," he added. त्तल ने परिषद अध्यक्षों के Singh said most of the disasters are human ला है पर उनकी जिम्मेदारी stigated problems. "If flooding instigated problems. "If flooding occurs, it's है। उन्होंने कहा कि mainly because of poor drainage systems in all mains because of poor drainage systems infil! hat city. The diversion of floods towards ur-उपल आणटा जीरियम कम करने को दिविटल मेपिंग की जिल्ला Speaking on the ban localities is an area of conce Speaking on the posses

विकास सम्बन्ध ीय सहारा, लखनऊ, रविवार, 7 अपनी वित्तीय पालिक अध्यक्षो स्थिति को सुदृढ़ कर



एस.पी. सिंह ने केन्द्र नवीन नगर विकास सम्बन्ध में व्याख्यान इनके तहत केन्द्र से आवश्यक है कि ना के क्रियान्वयन को निदेशक स्थानीय निव ने कहा कि राज्य सरव के अधूरे एजेंडे को के लिए कृत संकल्प की नवीन योजनाओं सरकार ने एक हस्ताक्षर किया है उ शीघ्र ही स्वीकृत परिये केन्द्र राज्य संरकार कराएगा।

प्रशिक्षण कार्यश क्षेत्रीय नगर एवं प केन्द्र के निदेशक

MAJOR ACHIEVEMENTS

The RCUES has been regularly undertaking academic activities in various aspects of urban government, namely, urban planning and development, urban finances, urban services, management of urban poverty alleviation programmes and management of urban environment, etc., since its inception in the constituent states. It has, however, diversified its activities in the above fields recently.

Some of the major achievements of RCUES are:

- Designated as implementing Agency for GOI- UNDP Project on "Capacity Development for Decentralised Urban Governance in U.P."
- Designated as **STATE RESOURCE CENTRE for JNNURM**, **UIDSSMT**, **BSUP** and **IHSDP** by the state Governments of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Jharkhand.
- Designated as **NODAL AGENCY** by Govt. of India for UIDSSMT for the cities/towns of the constituent states under the jurisdiction of Centre
- Designated as NODAL AGENCY for SWM by the Govt. of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Jharkhand
- Entrusted with the preparation of **REPORT CARD of ULBs** by the Govt. of U.P., M.P., Jharkhand and Bihar. The work for Class-1 cities in U.P. has been completed
- Designated as NODAL AGENCY for the Water Supply, sewerage and Drainage Projects implemented by Deptt. of Urban Development, Govt. of U.P.
- Designated as NODAL AGENCY for GIS and Computerization in ULBs by Govt. of U.P.
- Designated as NODAL AGENCY for introducing Double Entry Accounting System in ULBs by Govt. of U.P. AND M.P.
- Designated as IMPLEMENTING AGENCY for Administrative Restructuring of ULBs in U.P. and Jharkhand.
- Single enactment for allI the ULBs in U.P. being prepared by the Centre on the 'basis of **Model Municipal Law** prepared by Govt. of India.
- Conduct of Overseas Development Programmes for officers and administrators from South-east Asian and African countries.
- Nodal Agency for training under UNICEF sponsored Urban Basic Services (UBS) Programme for Bihar and U.P.
- Responsible for training and monitoring of Indore Habitat Improvement Project under the Overseas Development Administration (now known as DFID) project aided by the Government of U.K.
- Collaboration with the State Urban Development Agency (SUDA) to launch the UBSP programme in U.P.
- Designated as the State Training Institute for the State of U.P. for training of UBSP functionaries at different levels (sponsored by UNICEF).
- RCUES acted as the nodal implementing agency for the UNDP sponsored Project, "Capacity Development for Urban Governance' in U.P. and Uttaranchal.

FORTH COMING PUBLICATIONS

- Urban Governance in India (Challenges and Prospects) (in press)
- Public-Private Partnership in Urban Services (in press)

E-MAIL ADDRESSES OF FACULTY MEMBERS OF RCUES

Prof. Nishith Rai	-	Director	<u>;</u>	nkrai@hotmail.com, directorrcu	eslko@gmail.com
Shri R. Ramani, IAS	-	Hon. Advisor	:		
Shri B.B. Uppal	· .	Hon. Advisor			
Dr. U. Bagga		Jt. Director	:	urmila_rcues@yahoo.co.in	
Dr. R. Varmani	-	Jt. Director	:	richa_varmani@yahoo.co.in	
Dr. U.B. Singh	-	Jt. Director	:	ubsingh_56@yahoo.com	
Dr. Anjuli Mishra	-	Dy. Director	:	anjuli_lko@yahoo.co.in	
Dr. R. Narayan	-	Dy. Director	*	rajeev_1963@yahoo.com	
Dr. P. Iyer	-	Dy. Director	:	impadma@hotmail.com	
Dr. A.K. Singh		Asst. Director	· : .	awadhesh4@rediffmail.com	
Dr. Alka Singh	-	R.A.	;	alka_rcues@yahoo.co.in	

OUR IMPORTANT PUBLICATIONS

1.	Deliberative & Executive Wings in Local Government - Das, R.B. & Singh, D.P.	1968
2.	Training in Municipal Administration-RCUES	1968
3.	Towns of U.P., M.P., Bihar - Singh, D.P.	1968
4.	Urban Planning & Local Authorities - Das, R.B.	1970
5.	Coalition Government - Verma, M.S.	1971
6.	Urban Water Supply in U.P., M.P. and Bihar - Das, R.B.	1971
7.	Utility Services in a Metropolis - Das R.B. & Singh, D.P.	1974
8.	Property Taxes in Lucknow-RCUES	1975
9.	Municipal Taxation-RCUES	1976
10.	Ghaziabad-RCUES	1978
11.	Committee System in English Local Government - Sreeram, K.	1979
12.	Urban Conservation & Environment - Seth, J.L.	1988
13.	Situation Analysis of Urban Child in Uttar Pradesh - Seth, J.L. & Varmani, Richa	1988
14.	Urban Land Ceiling Act, U.P. - Bagga, Urmila	1989
15.	Privatisation of Municipal Services - Singh, U.B. (ed)	2001
16.	Assessing Training Needs in Urban Administration - Singh, U.B.	2003
17.	Urban Administration in India (Experiences of Fifty Year) - Singh, U.B. (ed.)	2004
18.	Capacity Development for Urban Governance - Dwivedi, S.K. & Narayan, Rajeev	2004
19.	Empowerment of Women in Urban Administration - Singh, U.B. (ed)	2006
20.	Urban Management - Rai, Nishith & Bagga, Urmila	2006
21.	Comparison of Cantonment Board and Nagar Nigam : A Case Study of Lucknow	2006
	- Varmani, Richa & Mishra, Anjuli	
22.	Sustainable Urban Management	2007
	- Rai, Nishith & Mishra, Anjuli	